घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 273- सोमवार 03- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

भारत में ड्रग्स सप्लाई आतंकी साजिश का हिस्सा...दुश्मन देश युवाओं को नशे में धकेलना चाहते हैं,हमें उनकी प्लानिंग नाकाम करनी है : पीएम मोदी

नई दिल्ली,02 अगस्त 2026। पीएम मोदी ने रविवार को'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भारत में ड्रग्स की सप्लाई दुश्मन देशों की आतंकी साजिश का हिस्सा है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संबोधन में कहा- दुश्मन देश भारतीय युवाओं को नशे के जाल में धकेलना चाहते हैं। इस साजिश को मिलकर नाकाम करना होगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा,जब देश का युवा शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के साथ नशे से भी दूर रहेगा।

उन्होंने बताया कि अगले 100 सप्ताह तक हर रविवार कला,संस्कृति,खेल और अन्य गतिविधियों के जरिए नशा मुक्ति का संदेश देशभर में पहुंचाया जाएगा। पीएम ने युवाओं से इस अभियान का नेतृत्व करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया।

नशा सपनों और परिवार दोनों को तोड़ देता है : पीएम मोदी ने कहा कि नशा युवाओं का फोकस भटकाकर उन्हें धीरे-धीरे उनके सपनों से दूर ले जाता है। आज भारत के युवा स्टार्टअप,एआई और स्पेस जैसे क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई युवा ड्रग्स की गिरफ्त में आ जाए तो सिर्फ उसका सपना ही नहीं, पूरा परिवार हार जाता है। नशा एक पिता के सपनों और बहन की उम्मीदों को भी तोड़ देता है।

दुश्मन देश ड्रग्स के जरिए युवाओं को निशाना बना रहे : मोदी

नशा केवल व्यक्ति को नहीं,बल्कि राष्ट्र की ताकत को भी कमजोर करता है। दुश्मन देश भारतीय युवाओं को ड्रग्स के जाल में फंसाने की साजिश रचते हैं। सरकार नशे के कारोबारियों और तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है।

ड्रग्स थोड़ी देर का हाई,लेकिन जिंदगीभर का नुकसान : मोदी

ड्रग्स कुछ समय के लिए हाई देता है,लेकिन करियर और फैमिली लाइफ को बर्बाद कर देता है। हमारे संतों और गुरुओं ने भी नशे से दूर रहने की सीख दी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो नशा इंसान की बुद्धि और विवेक छीन ले,वह उसे पतन की ओर ले जाता है।

नशे से बाहर निकले युवाओं को दूसरा मौका मिलना चाहिए : मोदी

नशे की लत से लड़कर बाहर निकलने वाले असली योद्धा हैं। किसी व्यक्ति का अतीत उसकी पहचान नहीं होता,बल्कि मुश्किलों से बाहर निकलने का उसका साहस उसकी असली पहचान होता है।

ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई कई गुना बढ़ी : पीएम मोदी

देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त की जा रही है और कार्रवाई पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' सुबह 11 बजे से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले देशभर के युवाओं ने एक साथ 'नशा मुक्त भारत' की शपथ ली। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देशभर के 28 हजार से ज्यादा स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। अभियान में 1 करोड़ से ज्यादा युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में 5 प्रमुख आध्यात्मिक गुरु-अम्मा, श्री श्री रविशंकर, दाजी,डॉ.चिन्मय पंड्या और स्वामी ब्रह्मविहारीजी भी वर्चुअली जुड़े। इसके अलावा कई मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

इंडोनेशिया में फेरी बोट में लगी आग..

लोग जान बचाने समुद्र में कूदे,5 की मौत

जकार्ता,02 अगस्त 2026। इंडोनेशिया के मादुरा द्वीप के पास रविवार सुबह एक फेरी बोट में आग लग गई। इसके बाद लोग जान बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। रॉयटर्स के मुताबिक, हादसे में कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई,जबकि 41 लोग अब भी लापता हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक फेरी में कुल 271 यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए बोट से समुद्र में कूद गए। दोपहर तक 225 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया,जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। फेरी ईस्ट जावा प्रांत के सुराबाया से साउथ सुलावेसी के मकासार जा रही थी। इसी दौरान मादुरा द्वीप के पास उसमें आग लग गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। फिलहाल लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

आग लगते ही फेरी में अफरा-तफरी मची

हादसे के दौरान के कुछ विजुअल्स सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें यात्री जलती हुई फेरी के अगले हिस्से की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना के सामने आए वीडियो में आग फैलने के बाद कई लोग घबराए हुए थे। रॉयटर्स के मुताबिक,बचाव दल आसपास के समुद्री इलाके में लापता लोगों की तलाश कर रहा है। सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के मुताबिक हादसे के बाद कई बचाव बोट्स और अन्य संसाधनों को मौके पर भेजा गया। राहत दल समुद्र में सर्च ऑपरेशन चला रहा है ताकि लापता लोगों का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन अभी जारी है और मृतकों या लापता लोगों की संख्या में बदलाव हो सकता है।

पप्पू यादव की प्रेस वार्ता में हंगामा...एक अज्ञात व्यक्ति के चप्पल फेंकने का आरोप,समर्थकों ने की पिटाई

नई दिल्ली,02 अगस्त 2026। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन'पप्पू'यादव के दिल्ली स्थित आवास पर शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उस समय हंगामा मच गया, जब एक अज्ञात व्यक्ति ने उन पर कथित तौर पर चप्पल फेंक दी।

घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद समर्थकों ने आरोपित को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। बाद में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने हस्तक्षेप कर उसे भीड़ से बाहर निकाला। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रेस वार्ता के दौरान एक व्यक्ति पप्पू यादव से कहता है कि भगवा कपड़ा पहन कर उन्होंने भगवान राम की मूर्ति को अयोध्या से सांसद अवधेश प्रताप के पैरों में रख दी, ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद उस शख्स ने अपनी चप्पल पप्पू यादव पर फेंक कर मारी। वीडियो में इसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ता चारों ओर से

थप्पड़ व घूंसों से उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उसकी शर्ट भी फट जाती है। वीडियो में इस दौरान पुलिसकर्मी बीच-बचाव कर उसे भीड़ से सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता दिखाई देता है। हालांकि जब तक उसे बाहर निकाला जाता तब तक पप्पू यादव के समर्थकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। वीडियो में पप्पू यादव भी अफरातफरी के बीच एक अन्य व्यक्ति को पकड़कर ले जाते हुए नजर आते हैं। चप्पल फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान अब तक सामने नहीं आई है। यह घटना ऐसे समय हुई है, जब राममंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर विवाद पहले से जारी है। शुक्रवार को संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया था। पप्पू यादव पुजारी के वेश में दानपात्र लेकर पहुंचे थे,जबकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतीकात्मक रूप से उसमें चंदा डाला था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने सांकेतिक रूप से'चोरी पकड़े जाने'का नाटक करते हुए पप्पू यादव की प्रतीकात्मक पिटाई भी की थी।

इस प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। वाराणसी में पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर जगदुरु बालक दास की शिकायत पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी,समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं,लखनऊ में सनातन रक्षा संगठन ने पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकाली और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया।

रेस्टोरेंट ने अपने नैपकिन पर भारत के नक्शे से नॉर्थ-ईस्ट को हटाया,बवाल मचा

ग्लासगो,02 अगस्त 2026। ग्लासगो के एक भारतीय रेस्टोरेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को डिनर के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद यह रेस्टोरेंट विवादों में घिर गया। 'मिस्टर सिंह इंडिया- द होम ऑफ करी' नाम के रेस्टोरेंट ने वहां आए एथलीट्स को ऐसे नैपकिन दिए, जिन पर भारत का आउटलाइन मैप बना था। जैसे ही ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने देखा कि मैप में देश के नॉर्थ-ईस्ट इलाके को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है,तो तुरंत नाराजगी जताई। बोरगोहेन ने न्यूज एजेंसी से कहा...'नैपकिन पर बने मैप में हमारा नॉर्थ-ईस्ट नहीं है। भारत का हर हिस्सा जरूरी है और उसे मैप में दिखाया जाना चाहिए।' बॉक्सिंग फैडरेशन ऑफ़ इंडिया (बीएफआई) के प्रेसिडेंट अजय सिंह ने स्टार बॉक्सर का समर्थन किया और पेपर नैपकिन पर मौजूद कुछ और बड़ी गलतियों की ओर इशारा किया,जिनमें जम्मू-कश्मीर का अधूरा नक्शा भी शामिल था। ग्लासगो में 'मिस्टर सिंह इंडिया' खाने-पीने की एक मशहूर जगह है,जहां अक्सर स्पोर्ट्स टीमें और बड़े-बड़े लोग आते रहते हैं। तीन दशकों से ज्यादा समय से इस रेस्टोरेंट ने ग्लासगो को पंजाबी विरासत और स्कॉटिश भावना के मेल से बनी एक पारिवारिक कहानी परोसी है। सिंह परिवार की चार पीढ़ियों द्वारा चलाया जा रहा यह रेस्टोरेंट,अपने खाने,मेहमाननवाजी और कम्युनिटी के जरिए पंजाबी खान-पान की विरासत और स्कॉटिश असर का मेल पेश करता है।

कार को ओवरटेक कर रुकवाया...कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या,प्रशासनिक महकमे में सनसनी

औरंगाबाद,02 अगस्त 2026। बिहार के औरंगाबाद जिले में डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या से प्रशासनिक महकमे में सनसनी फैल गई है। यह वारदात बारुण थाना क्षेत्र के धनौती पुल के पास शनिवार की देर रात हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार,विमल कुमार देर रात अपनी कार से डेहरी से पटना जा रहे थे। इसी दौरान धनौती पुल के समीप अज्ञात अपराधियों ने उनकी कार को ओवरटेक कर रुकवा लिया। बदमाशों ने पहले चालक को अपने कब्जे में लिया और फिर विमल कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की। उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल विमल कुमार को तत्काल जमुहार स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया,जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि मृतक के शरीर पर मारपीट और धारदार हथियार से हमले के गंभीर निशान मिले हैं। उन्होंने कहा कि गोली लगने की बात अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि हत्या के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

कर्नाटक में जल्द हो सकता है कैबिनेट विस्तार

डीके शिवकुमार और कांग्रेस आलाकमान की दिल्ली में बैठक,20 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं

बेंगलुरु,02 अगस्त 2026। कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शपथ लेने के करीब दो महीने बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। शिवकुमार और राज्य के कई कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आलाकमान से मुलाकात की। यहां कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 20 नए मंत्रियों के नाम आज तय हो सकते हैं। वहीं,अगले सप्ताह शपथ ग्रहण हो सकता है। अभी कैबिनेट में सीएम समेत 14 मंत्री हैं।

कर्नाटक की कैबिनेट में 34 मंत्री शामिल हो सकते हैं : डीके शिवकुमार ने 3 जून को

उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर और 12 अन्य मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। कर्नाटक में संवैधानिक रूप से मुख्यमंत्री सहित कुल 34 मंत्री हो सकते हैं, जिसके चलते अभी भी लगभग 20 पद खाली हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी हाईकमांड जातीय, सामुदायिक और नए-पुराने नेताओं में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। इसके अलावा, डीके शिवकुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के गुटों की ओर से अलग-अलग नाम सुझाए जा रहे हैं।

कर्नाटक की राजनीति में वोक्कालिगा,लिंगायत और कुरबा समाज अहम

कर्नाटक में लिंगायत (लगभग 17%) सबसे बड़ा समुदाय है, जबकि दक्षिण कर्नाटक में वोक्कालिगा (लगभग 15%) का दबदबा है, जिसका नेतृत्व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार करते हैं। वहीं,कुरबा (लगभग 7-8%) समाज एक प्रमुख पिछड़ा वर्ग है,जिससे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आते हैं और वे अपनी अहिंदा राजनीति के जरिए मजबूत पकड़ रखते हैं। सिद्धारमैया के बेटे डॉ. यतींद्र सिद्धारमैया को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है।

तमिलनाडु में पोल्लाची के पास खड़े ट्रक से टकराई कार,एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

कोयंबटूर,02 अगस्त 2026। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में पोल्लाची के निकट सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से कार की जोरदार टक्कर होने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका। पुलिस के अनुसार,कोयंबटूर जिले के मदुक्करई एमएलए स्ट्रीट निवासी कनकराज एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। उनके परिवार में पत्नी उमा महेश्वरी, बड़ी बेटी आरती और छोटी बेटी नर्मदा थीं। रविवार को कनकराज अपने परिवार तथा दूर के रिश्तेदार रामन के साथ कार से उदुमलपेट स्थित अपने कुलदेवता मंदिर में दर्शन कर

वापस घर लौट रहे थे। कार कनकराज स्वयं चला रहे थे। दोपहर के समय जब उनकी कार पोल्लाची के पास नल्लाम्पल्ली इलाके से गुजर रही थी, तभी वह अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कनकराज, उनकी पत्नी उमा महेश्वरी,दोनों बेटियां आरती और नर्मदा तथा रिश्तेदार रामन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

अनुशासनहीनता पर बसपा ने अशोक सिद्धार्थ और रणधीर सिंह बेनीवाल को पार्टी से निकाला

लखनऊ,02 अगस्त 2026। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अनुशासनहीनता और पार्टी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ और पार्टी के को-ऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। अशोक सिद्धार्थ बसपा प्रमुख मायावती के समधी तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता आकाश आनंद के ससुर हैं। रविवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी सिलसिलेवार पोस्ट में मायावती ने कहा कि अशोक सिद्धार्थ को पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण के मुद्दे पर प्रदेश नेतृत्व के साथ तालमेल नहीं बैठा पाने और अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निकाला गया था। बाद में इस शर्त पर उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल किया गया कि वे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। मायावती के अनुसार, दोबारा जिम्मेदारी मिलने के बाद भी अशोक सिद्धार्थ अपने

दायित्वों का निर्वहन अपेक्षित ढंग से नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी उनके खिलाफ पार्टी के दिशा-निर्देशों की अनदेखी और अनुशासनहीनता की शिकायतें लगातार मिलती रहीं। कई बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद सुधार नहीं होने पर पार्टी और आंदोलन के हित में उन्हें स्थायी रूप से निष्कासित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब उन्हें भविष्य में दोबारा पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। बसपा प्रमुख ने अपने पोस्ट में बताया कि सहारनपुर निवासी एवं पार्टी के को-ऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी अनुशासनहीनता और पार्टी निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में निष्कासित किया गया है।

किसने की दिपके की फडिंग...आरटीआई एक्टिविस्ट ने पूछा,अमेरिका जाने का खर्च कहां से आया

सूरत,02 अगस्त 2026। गुजरात के सूरत निवासी एक सूचना के अधिकार कार्यकर्ता ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके तथा उनके परिवार के वित्तीय मामलों की जांच की मांग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग और आयकर विभाग को पत्र भेजा है। साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा प्रदर्शनकारियों के लिए घोषित एक करोड़ रुपये के कानूनी सहायता कोष की भी जांच कराने की मांग की गई है। आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने अपने पत्र में कहा है कि अभिजीत दिपके के पिता भगवानराव दिपके महाराष्ट्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी रहे हैं। ऐसे में यह जांच की जानी चाहिए कि उन्होंने अपने पुत्र की विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक धनराशि किस प्रकार जुटाई। उन्होंने संबंधित एजेंसियों से इस मामले की वित्तीय जांच कराने का अनुरोध किया है।

पाकिस्तान में आत्मघाती हमला,14 की मौत

खैबर पख्तूनख्वा में युवक ने थाने में जाकर ब्लास्ट किया,20 लोग गंभीर रूप से घायल

इस्लामाबाद,02 अगस्त 2026। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में रविवार को एक पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मघाती हमला हुआ। इसमें 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक,हमले के समय पास के काबल चौक पर आतंकवाद के खिलाफ शांति रैली चल रही थी। स्वात के जिला पुलिस अधिकारी उमर खान के ने बताया कि इसी दौरान एक युवक काबल पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचा। पुलिस वालों ने उसे रोककर तलाशी लेने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। इससे पहले पुलिस हरकत में आती, युवक को खुद को ब्लास्ट कर दिया। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है।

लोग आतंकवाद के खिलाफ रैली निकाल रहे थे : धमाके से पहले रविवार को कई लोग आतंकवाद के खिलाफ शांति रैली निकाल जा रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्वात में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं की निंदा की। डॉन के मुताबिक,प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनके आंदोलन का एक ही मकसद है,इलाके में शांति लौटाना और आतंकवाद का खात्मा करना। उन्होंने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है।

अगर असुरक्षा का माहौल जारी रहा तो लोगों में बड़ा जनआक्रोश पैदा हो सकता है। प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करता है,जबकि स्वात के पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी खुलेआम सक्रिय हैं।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने घटना की निंदा की : खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घटना की निंदा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक से रिपोर्ट की मांग की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, शांति के दुश्मनों को उनके नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं,खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी धमाके की निंदा करते हुए मृतकों के प्रति शोक जताया।

संपादकीय

गाली सिखाने वाला स्कूल नहीं,हमारा समाज है...

शिक्षक सिर्फ आसान निशाना बन गया

एक स्कूल में बच्चों से सजा के तौर पर गालियां लिखवाई गईं। वीडियो सामने आया और पूरा देश मानो फैसला सुनाने बैठ गया। किसी ने कहा शिक्षिका को बर्खास्त करो,किसी ने कहा जेल भेजो, किसी ने स्कूल की मान्यता खत्म करने की मांग कर दी।

लेकिन एक सवाल किसी ने नहीं पूछा...आखिर बच्चे गालियां सीखते कहां से हैं? क्या किसी स्कूल की किताब में मां-बहन की गालियां पढ़ाई जाती हैं? क्या कोई शिक्षक कक्षा में खड़ा होकर बच्चों को अश्लील भाषा सिखाता है? जवाब सबको पता है–नहीं। फिर भी कटघरे में सिर्फ शिक्षक है।

बच्चा दिन के पांच-छह घंटे स्कूल में रहता है,लेकिन बाकी समय घर,गली, मोहल्ले, मोबाइल और सोशल मीडिया के बीच। घर में पिता गाली देता है, सड़क पर लोग गाली देकर झगड़ते हैं,क्रिकेट खेलते बच्चे गाली देते हैं,बारात में बजने वाले गानों में गालियां हैं,फिल्मों और वेब सीरीज में गालियां हैं,यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गालियां मनोरंजन बन चुकी हैं।
लेकिन इन सब पर समाज चुप है।

सोशल मीडिया पर हर दिन ऐसे वीडियो वायरल होते हैं,जहां लोग खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी किसी ने मांग की कि इन लोगों के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई हो जैसी एक शिक्षिका के खिलाफ मांग रहे हैं?
समस्या यह नहीं कि शिक्षिका से गलती हुई या नहीं। यदि अनुशासन के नाम पर गलत तरीका अपनाया गया है,तो नियम के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या कार्रवाई का मतलब यह है कि समाज अपनी सारी जिम्मेदारी शिक्षक पर डालकर मुक्त हो जाए?
सच यह है कि हमने शिक्षक को गुरु से कर्मचारी बना दिया है।

एक समय था जब शिक्षक का सम्मान परिवार से शुरू होता था। बच्चे गलती करते थे तो अभिभावक कहते थे–सर,जरूरत पड़े तो डांटिए,समझाइए, सुधारिए। आज स्थिति उलट गई है। शिक्षक की आवाज ऊंची हो जाए तो शिकायत,हल्का अनुशासन कर दे तो वीडियो,कोई काम बता दे तो कैमरे लेकर मीडिया पहुंच जाती है।

दूसरी तरफ वही बच्चा घर में घंटों मोबाइल पर क्या देख रहा है,किससे क्या सीख रहा है,इसकी चिंता कम ही दिखाई देती है।
सबसे बड़ा सवाल मीडिया से भी है।

यदि स्कूल में बच्चा झाड़ू लगा रहा हो,पानी भर रहा हो या कुर्सी उठा रहा हो तो कैमरे पहुंच जाते हैं। लेकिन शादी-ब्याह में डीजे पर बजते अश्लील और गाली-गलौज वाले गीतों पर शायद ही कभी कोई बहस होती है। सार्वजनिक स्थानों पर गालियां देते लोगों को देखकर भी कैमरे उतने आक्रामक नहीं होते।
क्या इसलिए कि वहां टीआरपी कम है?

समाज को तय करना होगा कि वह बच्चों को कैसी भाषा और कैसा वातावरण देना चाहता है। यदि घर,गली,मोबाइल और मनोरंजन के हर माध्यम से बच्चा गालियां सीख रहा है,तो केवल एक शिक्षिका को सजा देकर हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते।
कड़वा सच यही है कि बच्चे वही बोलते हैं,जो वे सुनते हैं।
अगर हमें सचमुच गालियां खत्म करनी हैं,तो शुरुआत स्कूल से नहीं,अपने घर से करनी होगी। क्योंकि गाली सिखाने वाला कोई स्कूल नहीं...हमारा समाज है।

जब अदालतें जवाब मांगती हैं,तब व्यवस्था में भरोसा बढ़ता है...

रवि सिंह
कोरिया,छत्तीसगढ़

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

* जवाबदेही तय होगी,तभी न्याय व्यवस्था मजबूत होगी...
* न्यायालय की सख्तीः व्यवस्था को जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम
* न्याय केवल फैसला नहीं,जवाबदेही भी चाहता है...
* न्यायपालिका का संदेशः लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी...
* सरकारी लापरवाही पर न्यायालय की सख्ती लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत...
* न्याय व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी तो जनता का भरोसा भी मजबूत होगा...
* समय पर न्याय के लिए जवाबदेही जरूरी है,अदालतों की सक्रियता ने दिया स्पष्ट संदेश...न्यायिक प्रक्रिया से समझौता नहीं...

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यायपालिका मानी जाती है, सरकारें बदलती है,अधिकारी बदलते हैं,नीतियां बदलती हैं,लेकिन यदि जनता का विश्वास किसी संस्था पर सबसे अंत तक बना रहता है तो वह न्यायपालिका है,लोकतांत्रिक व्यवस्था तीन स्तंभों पर खड़ी मानी जाती है

विधायिका,कार्यपालिका और न्यायपालिका,इनमें न्यायपालिका वह अंतिम संस्था है,जहां नागरिक तब पहुंचता है जब उसे लगता है कि व्यवस्था के दूसरे दरवाजे उसके लिए बंद हो चुके हैं,इसलिए न्यायालय का हर आदेश केवल एक मुकदमे का फैसला नहीं होता,बल्कि व्यवस्था को दिया गया एक संदेश भी होता है,यही कारण है कि जब किसी नागरिक को हर दरवाजा बंद दिखाई देता है,तब वह अंततः अदालत का दरवाजा खटखटाता है,लेकिन न्याय केवल फैसला सुनाने का नाम नहीं है, न्याय एक प्रक्रिया है,यदि वह प्रक्रिया ही बार-बार बाधित होती रहे,यदि विवेचक समय पर न्यायालय न पहुंचे,यदि सरकारी अधिकारी समन और वारंट के बावजूद गवाही देने न आएं,यदि वर्षों तक मुकदमे केवल इसलिए लंबित रहें क्योंकि जांच एजेंसी अपना दायित्व समय पर नहीं निभा रही है,तब सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं रह जाता कि आरोपी दोषी है या निर्दोष? सबसे बड़ा प्रश्न यह बन जाता है कि क्या व्यवस्था स्वयं अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है? छत्तीसगढ़ में हाल ही में दो न्यायिक घटनाक्रमों ने यही संदेश दिया है कि अदालतें अब केवल मुकदमों का अंतिम निर्णय देने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि वे यह भी देख रही हैं कि न्यायिक प्रक्रिया कहीं सरकारी लापरवाही की भेंट तो नहीं चढ़ रही,एक मामले में उच्च न्यायालय को पुलिस महानिदेशक से व्यक्तिगत शपथपत्र मांगना पड़ा,क्योंकि विवेचक के न्यायालय में उपस्थित न होने से मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो रही थी,दूसरे मामले में एक सत्र न्यायालय ने गवाही के लिए लगातार अनुपस्थित रहने वाले पुलिस अधिकारी पर आर्थिक दंड लगाया और राशि वेतन से काटने का आदेश दिया, यह दोनों आदेश केवल दो व्यक्तियों या दो मामलों की कहानी नहीं हैं,यह पूरी व्यवस्था के लिए एक चेतावनी हैं कि न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने वाली लापरवाही अब केवल प्रशासनिक कमजोरी नहीं मानी जाएगी,बल्कि जवाबदेही का विषय बनेगी।

यह घटनाएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लंबे समय से आम नागरिकों के बीच एक धारणा बनती रही है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही से मुकदमे लंबित होते हैं,तो उसकी जवाबदेही शायद ही कभी तय होती है, तारीखें बढ़ती रहती हैं,गवाह लौटते रहते हैं,पीड़ित इंतजार करता रहता है और कई बार न्याय की गति सरकारी तंत्र की उदासीनता की भेंट चढ़ जाती है,पुलिस विवेचना किसी भी आपराधिक मुकदमे की आधारशिला होती है,यदि विवेचक समय पर न्यायालय नहीं पहुंचेगा, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेगा या न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करेगा,तो सबसे बड़ा नुकसान उस व्यक्ति को होगा जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है,इसलिए न्यायालय का हस्तक्षेप केवल किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं,बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा की रक्षा का प्रयास है, इन आदेशों का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि उन्होंने एक संदेश दिया है–सरकारी पद किसी को न्यायालय से ऊपर नहीं बनाता,चाहे अधिकारी कितना भी व्यस्त क्यों न हो,न्यायालय के आदेशों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है,यदि किसी कारणवश उपस्थित होना संभव नहीं है,तो न्यायालय को समय पर सूचित करना भी उसी जवाबदेही का हिस्सा है, यह भी सही है कि पुलिस अधिकारियों पर कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, गंभीर अपराधों की विवेचना,कानून-व्यवस्था,वीआईपी ड्यूटी और अन्य प्रशासनिक दायित्व उनके कार्य का हिस्सा हैं,लेकिन यही कारण उन्हें न्यायालय के आदेशों की अनदेखी करने का स्वतः अधिकार नहीं देता,न्यायिक प्रक्रिया भी शासन व्यवस्था का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना अपराध की जांच,इन घटनाओं से एक और सकारात्मक संदेश जाता है–न्यायपालिका अब केवल अंतिम फैसला सुनाने वाली संस्था नहीं,बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की गुणवत्ता और समयबद्धता पर भी निगरानी रख रही है,यदि यह प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है,तो इसका लाभ केवल न्यायालयों को नहीं,बल्कि पूरे समाज को मिलेगा,हालांकि जवाबदेही केवल न्यायालय की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार को भी ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। यदि किसी अधिकारी के कारण मुकदमे बार-बार प्रभावित हो रहे हैं,तो केवल न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा करने के बजाय विभागीय स्तर पर भी समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, इससे न्यायालयों का समय बचेगा और नागरिकों का विश्वास भी मजबूत होगा, आज जब न्यायालय यह संदेश दे रहे हैं कि लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, तब कार्यपालिका के लिए भी यह आत्ममंथन का अवसर है,कानून का शासन तभी प्रभावी माना जाएगा, जब जांच एजेंसियां,अभियोजन और न्यायपालिका तीनों समान गति और समान जिम्मेदारी के साथ काम करें, न्याय केवल निर्णय देने से नहीं मिलता, बल्कि समय पर निर्णय मिलने से मिलता है,यदि न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने वाली लापरवाही पर इसी तरह जवाबदेही तय होती रही,तो निश्चित रूप से आम नागरिक का न्यायपालिका पर भरोसा और अधिक मजबूत होगा, यही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी सफलता भी है।

न्याय की सबसे बड़ी दुश्मन अपराधी नहीं, देरी है–भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा लंबित मुकदमे रहे हैं,जब कोई मुकदमा दस-दस वर्ष चलता है,तब अक्सर लोग न्यायपालिका को दोष देते हैं,लेकिन शायद ही कभी यह चर्चा होती है कि उन मुकदमों में कितनी तारीखें इसलिए बढ़ीं क्योंकि पुलिस समय पर केस डायरी नहीं लाई,विवेचक उपस्थित नहीं हुआ,गवाह पेश नहीं हुए या सरकारी पक्ष ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, एक तारीख केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं होती,उस तारीख के साथ जुड़ा होता है पीड़ित का इंतजार,आरोपी का भविष्य,गवाह की उम्मीद,समाज का न्याय पर विश्वास,यदि किसी सरकारी अधिकारी की लापरवाही से एक तारीख बढ़ती है,तो उसका प्रभाव केवल एक दिन का नहीं होता,कई बार मुकदमे महीनों और वर्षों पीछे चले जाते हैं,यही कारण है कि जब न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो वे केवल एक अधिकारी को नहीं,बल्कि पूरी व्यवस्था को संदेश देते हैं कि न्याय में देरी भी न्याय के साथ अन्याय हो सकती है।

क्या पुलिस की जिम्मेदारी केवल अपराध दर्ज करना है?– आम तौर पर पुलिस की भूमिका अपराध दर्ज करने और जांच करने तक सीमित समझी जाती है, लेकिन वास्तव में पुलिस की जिम्मेदारी तब तक समाप्त नहीं होती जब तक न्यायालय में मुकदमे का तार्किक निष्कर्ष नहीं निकल जाता,विवेचक ही वह व्यक्ति होता है जिसने घटनास्थल देखा,जिसने साक्ष्य एकत्र किए,जिसने गवाहों के बयान दर्ज किए,जिसने आरोपपत्र तैयार किया,यदि वही व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा,तो अभियोजन की पूरी श्रृंखला कमजोर पड़ सकती है,यही कारण है कि न्यायालय विवेचक की उपस्थिति को औपचारिकता नहीं,बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं।

न्यायपालिका का बदलता दृष्टिकोण–पिछले कुछ वर्षों में देशभर की अदालतों ने समयबद्ध न्याय पर अधिक जोर देना शुरू किया है,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,डिजिटल केस मैनेजमेंट, ई-कोर्ट और समयबद्ध ट्रायल जैसे प्रयास इसी सोच का हिस्सा हैं,अब यदि न्यायालय सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने लगे हैं,तो यह उसी सुधार प्रक्रिया का अगला चरण माना जा सकता है।

लोकतंत्र में सबसे मजबूत संदेश–लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां कोई भी संस्था पूरी तरह निरंकुश नहीं है,कार्यपालिका पर न्यायपालिका की निगरानी लोकतांत्रिक संतुलन का हिस्सा है,यदि न्यायालय यह पूछते हैं कि आप समन के बावजूद क्यों नहीं आए? आपके कारण मुकदमा क्यों रुका? आपने आदेश का पालन क्यों नहीं किया? तो यह किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि संविधान द्वारा स्थापित जवाबदेही की व्यवस्था का संचालन है।

पीड़ित को भी अधिकार है कि मुकदमा समय पर पूरा हो–भारतीय न्याय व्यवस्था में अक्सर आरोपी के अधिकारों की चर्चा होती है, जो स्वाभाविक भी है, लेकिन पीड़ित के भी अधिकार हैं, उसे भी यह अधिकार है कि उसका मुकदमा वर्षों तक न लटके,उसे बार-बार अदालत के चक्कर न लगाने पड़ें, सरकारी अधिकारी की लापरवाही का बोझ उस पर न पड़े,जब न्यायालय ऐसे मामलों में सख्ती दिखाते हैं, तब वे केवल कानून लागू नहीं करते,बल्कि पीड़ित के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं।

संस्कारों का हस्तांतरण अगली पीढ़ी को ठीक तरीके से न हो,तो उस समाज का क्षय होना निश्चित है...

अश्लीलता दबे पांव नहीं,सीना तानकर इंस्टा यूट्यूब के दरवाजे आपके घर तक आई है...

संतोषदास 'सरल'
अम्बिकापुर,सरगुजा (छ.ग.)

इन दिनों नीट पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के हिंसक और अश्लील विरोध प्रदर्शन को लेकर पूरे सोशल मीडिया में प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं के अश्लील गाली-गलौज वाले वीडियो तैर रहे हैं। कुछ लोग ZEN-Z के इस शर्मनाक कृत्य को नया ट्रेंड बताकर महिमामंडित कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे नए भारत के युवाओं की ताकत बता रहे हैं। भारतीय समाज के बीच से निकलकर आए ये किशोर युवा आखिर कौन हैं जिन्हें मान,मर्यादा,परंपरा,संस्कारों का भान नहीं? याद रखिए ! ये अश्लीलता दबे पांव नहीं,सीना तानकर इंस्टा यूट्यूब के दरवाजे आपके घर तक आई है,और विडंबना देखिए आप इसे ZEN-Z की नई सोंच कहकर इसका स्वागत व अभिनंदन कर रहे हैं। आप किसी सरकार,किसी राजनीतिक दल या फिर किसी विचारधारा के विरोधी तो हो सकते हैं परंतु जिस समाज में आप पले-बढ़े और जिस समाज से संस्कार लेकर आपने जीने का तौर-तरीका सीखा आप उसके विरोधी नहीं हो सकते।
जन्तर-मन्तर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम पर पूरे देश ने जो अश्लीलता,नग्नता और भौंडापन देखा उसने देश के पंद्रह-सत्रह साल के ZEN-Z का एक भयावह,विकृत स्वरूप प्रस्तुत कर पूरे भारतीय समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भारतीय समाज पढ़े लिखे युवाओं की असभ्यता पर हतप्रभ और किंकर्तव्यविमूढ़ है। अपने परदादा की उम्र के किसी व्यक्ति के लिए ऐसी गंदी गालियां जिसे कानों से सुन पाना सम्भव ना हो उसे युवा किशोर लड़कियों के मुख से सुननी पड़ जाए तो समाज को चिंता नहीं,चीत्कार करने की आवश्यकता है। ZEN-Z के ऐसे अमर्यादित असामान्य व्यवहार पर यदि आप इसलिए खुश हैं कि आप किसी व्यक्ति या सरकार के विरोधी हैं और विरोध में तो सब जायज है वाली बात पर यकीन करते हैं तो याद रखिए आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं,सीने पर खंजर चला रहे हैं। समाज की बुराइयों को देखकर खुश होने वाले व्यक्ति के परिवार की संतानें कभी न कभी दुनिया के सामने अपने परिवार को शर्मिन्दा कर कहीं का नहीं छोड़ती। किसी भी समाज में व्याप्त संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बहुत सहेजकर व संभालकर सौंपे जाते हैं और यदि संस्कारों का हस्तांतरण अगली पीढ़ी को ठीक तरीके से न हो तो उस समाज का क्षय होना निश्चित है।

जंतर-मंतर के अश्लील प्रदर्शन को युवाओं में उपजा भारी आक्रोश बताने वाले ये भूल जाते हैं कि इससे भी कई गुना ज्यादा आक्रोश निर्भया कांड को लेकर वर्ष 2012 में था जिसने देश के हर गली मुहल्ले को आंदोलित किया था। देश में भ्रष्टाचार को लेकर अन्ना हज़ारे के विरोध प्रदर्शन से बड़ा ऐसा कोई अनशन या आंदोलन नहीं हुआ जिसका समर्थन देश के प्रत्येक युवा व नागरिकों ने किया हो,परंतु मजाल है कि प्रदर्शन में भाग लेने वाले किसी भी युवा की तख्ती पर तत्कालीन सरकार या व्यवस्था के लिए किसी ने गालियां लिखी हुई देखी हो? या किसी प्रदर्शनकारी युवा की जुबान से पुलिस प्रशासन व सरकार के विरुद्ध गंदी अश्लील गालियों की बौछार किसी ने देखी सुनी हो? रामलीला मैदान और जंतर-मंतर दोनों आंदोलनों की कोई तुलना नहीं क्यूंकि अन्ना आंदोलन अपने आदर्श, मर्यादा व अनुशासन के लिए याद किया जाता है तो जंतर-मंतर का नीट पेपर लीक आंदोलन अपनी फूहड़ता और अश्लीलता के लिए। जंतर-मंतर का आंदोलन खत्म होने के बाद से देश के Zen-Z की सोंच और दिशा क्या है? यह चिंतन पूरे देश और समाज को भयाक्रांत कर रही है। कहते हैं हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी से बेहतर होती है, क्या वर्तमान पीढ़ी के संदर्भ में भी यह बात कही जा सकती है? क्या सदियों से चले आ रहे मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में संस्कारों के बिना केवल आधुनिक तकनीक और AI ज्ञान के सहारे वर्तमान पीढ़ी अपनी पहचान बनाने की दिशा में अब बहुत आगे निकल चुकी है? क्या आधुनिक तकनीक के प्रभाव में वर्तमान पीढ़ी स्वच्छंद होकर लोक-लाज के भय से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है? इन सवालों के जवाब यदि आज नहीं ढूँढे गए तो यकीन मानिए आने वाले समय में भारतीय समाज की पहचान उनके संस्कार व आदर्श अपना अस्तित्व बचाने संघर्ष करते दिखेंगे..!!

हाईवे के गड्ढों का पंजीकरण

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

देश की अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही थी। सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था राजस्व कहाँ से आए? करदाताओं की जेबें पहले ही राष्ट्रहित में इतनी हल्की हो चुकी थीं कि उनमें अब हवा ही टैक्स देकर ही प्रवेश कर सकती थी। पेट्रोल,डीज़ल,गैस,बिजली,पानी सब अपना-अपना राष्ट्रधर्म निभा चुके थे। अब ज़रूरत किसी ऐसे स्रोत की थी जो जनता की आँखों के सामने पड़ा हो,लेकिन जिस पर अभी तक सरकार की नज़र न पड़ी हो। राजधानी में देश के नामी प्रबंधन संस्थानों के टैलेंटेड एमबीए विशेषज्ञ बुलाए गए। पाँच सितारा होटल में कई दिन तक राष्ट्र की चिंता पर गहन मंथन हुआ। कॉफी के कप बदलते रहे,प्रस्तुतियाँ चलती रहीं और अंततः निष्कर्ष निकला कि भारत की असली पूँजी सड़कों पर नहीं,सड़कों के गड्ढों में दबी है। सड़क तो केवल खर्च कराती है, गड्ढा कमाई कराता है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि देश के प्रत्येक गड्ढे का बाकायदा पंजीकरण किया जाए। उसका नाम, पता, लंबाई, चौड़ाई,गहराई और दुर्घटना कराने की क्षमता सरकारी अभिलेखों में दर्ज हो। जो गड्ढा केवल मोटरसाइकिल वाले को गिरा दे, वह बी श्रेणी का। जो कार के यात्रियों की रीढ़ की हड्डी को राष्ट्रभक्ति का अनुभव करा दे,वह ए श्रेणी का। और जिसमें ट्रक भी पूरे सम्मान के साथ उतर जाए, उसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया जाए और गड्ढा जनता से राजस्व वसूली का बड़ा साधन बन जाना चाहिए।

एक अधिकारी ने संकोच से पूछा, इतनी मेहनत क्यों? विशेषज्ञ मुस्कराया, सर,आज डेटा ही नया तेल है और गड्ढा उसका कुआँ। बस,फिर क्या था! मंत्रालय में फाइलें इतनी तेज़ दौड़ीं कि वर्षों से सोई सड़कें भी शर्मा गईं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए बोर्ड लग गए धीरे चलें, आगे सरकार की आय का स्रोत सक्रिय है। जिलाधिकारियों को लक्ष्य दिया गया कि प्रत्येक जिले में गड्ढों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि सुनिश्चित की जाए। जिन जिलों में सड़कें गलती से समतल पाई गई,वहाँ के अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा गया कि उन्होंने विकास की इस अभिनव योजना को विफल करने का दुस्साहस कैसे किया। पंचायतों को निर्देश मिला कि उत्कृष्ट गड्ढों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। सूचना-पट्ट पर लिखा गय यह गड्ढा विगत पंद्रह वर्षों से निरंतर राष्ट्रसेवा में समर्पित है। अनेक वाहनों,यात्रियों और सस्पेंशनों को सफलतापूर्वक प्रभावित कर चुका है।

कुछ जनप्रतिनिधियों ने गर्व से घोषणा की कि उनके क्षेत्र के गड्ढे पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। बरसात में बिना सरकारी सहायता के फैल जाते हैं,गर्मी में विश्राम करते हैं और चुनाव आते ही फिर पूरे उत्साह से सक्रिय हो जाते हैं। उधर पुलों की दरारों को भी नया सम्मान मिला। इंजीनियरों ने प्रेस वार्ता में बताया कि दरारें कमजोरी नहीं, बल्कि संरचना की लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति हैं। हर पुल को भी अपनी बात कहने का अधिकार है। एक बूढ़ा किसान हाथ जोड़कर बोला, साहब,सड़क कब बनेगी? अधिकारी ने उसे दया से देखा,जैसे कोई प्रोफ़ेसर पहली कक्षा के छात्र को क्वांटम भौतिकी समझा रहा हो,बाबा,तुम बहुत पुराने विचारों में जी रहे हो। अब सड़कें नहीं बनतीं, अवसर बनते हैं। यह गड्ढा तुम्हारे गाँव की अर्थव्यवस्था बदल देगा। पंचर वाला कमाएगा,मैकेनिक कमाएगा, अस्पताल कमाएगा,दवा वाला कमाएगा। विकास का पूरा चक्र इसी में घूमता है। किसान चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी टूटी हुई बैलगाड़ी का पहिया भी शायद सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दे रहा है। सरकार ने अगला कदम भी सोच लिया। जो नागरिक गड्ढे की शिकायत करेगा,उससे पूछा जाएगा क्या आप विकास-विरोधी मानसिकता रखते हैं? क्योंकि जिस वस्तु से सरकार को राजस्व मिलने की संभावना हो, उसकी आलोचना करना लगभग राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा।
बजट का दिन आया। वित्त मंत्री ने गर्व से घोषणा की इस वर्ष सकल गड्ढा उत्पाद में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। दुर्घटनाओं का ग्राफ ऊपर गया है,इसलिए विकास दर भी उत्साहजनक है। पूरा सदन मेज़ें थपथपा रहा था। केवल जनता चुप थी। वह तालियाँ नहीं बजा रही थी,क्योंकि उसके दोनों हाथ अपनी गाड़ी के टूटे हुए सस्पेंशन और बढ़ती ईएमआई का हिसाब लगाने में व्यस्त थे।धीरे-धीरे देश में यह सिद्धांत स्थापित हो गया कि समस्या का समाधान करना दूरदर्शिता नहीं,उसे जीवित रखना आर्थिक बुद्धिमत्ता है। जो गड्ढा भर दिया जाए,वह केवल मिट्टी है; जो गड्ढा छोड़ दिया जाए,वही भविष्य का राजस्व है,और जिस दिन किसी राष्ट्र में सड़क से अधिक गड्ढे की उपयोगिता सिद्ध होने लगे,उस दिन समझ लीजिए कि सड़क नहीं टूटी है शासन की प्राथमिकताएँ टूट चुकी हैं। डामर केवल सड़क से नहीं उखड़ा,जवाबदेही भी उसके साथ बह गई है। तब विकास के भाषण चिकने रह जाते और जनता की राहें हमेशा की तरह ऊबड़-खाबड़।

उम्र के अनुसार खाइए : जीवन के हर पड़ाव के लिए सही पोषण

डॉ विजय गर्ग,मलोट पंजाब

अक्सर कहा जाता है,जैसा अन्न,वैसा मन और वैसा तन। यह कहावत आज के समय में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है,शरीर की आवश्यकताएँ भी बदलती जाती हैं। बचपन, किशोरावस्था,युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था–हर चरण में शरीर को अलग-अलग प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए एक ही प्रकार का भोजन पूरी जिंदगी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। "Eat Your Age" का अर्थ है अपनी उम्र और शरीर की जरूरतों के अनुसार भोजन का चुनाव करना।
बचपन जीवन की वह अवस्था है जब शरीर और मस्तिष्क का सबसे तेज़ विकास होता है। इस समय बच्चों को प्रोटीन,कैल्शियम,आयरन,विटामिन और स्वस्थ वसा से भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है। दूध,दही,अंडे,दालें, हरी सब्जियाँ,फल और साबुत अनाज उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि बचपन में संतुलित आहार मिले तो भविष्य में अनेक बीमारियों से बचाव संभव है।

किशोरावस्था में शरीर तेजी से बढ़ता है और हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। इस उम्र में ऊर्जा,प्रोटीन,आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता बढ़ जाती है। विशेष रूप से किशोरियों के लिए आयरन युक्त भोजन अत्यंत आवश्यक है ताकि एनीमिया से बचा जा सके। दुर्भाग्यवश आज के अनेक किशोर जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक और पैकेज्ड स्नैक्स को प्राथमिकता देते हैं,जिससे मोटापा,पोषण की कमी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ बढ़ रही हैं। घर का ताजा भोजन,मौसमी फल,सूखे मेवे और पर्याप्त पानी इस आयु के लिए सर्वोत्तम हैं। युवावस्था में पढ़ाई,नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण लोग अक्सर भोजन को नजर अंदाज कर देते हैं। नाश्ता छोड़ना,देर रात खाना और फास्ट फूड पर निर्भर रहना आम बात हो गई है। जबकि यही वह समय है जब स्वस्थ खान-पान की आदतें भविष्य के स्वास्थ्य की नींव रखती हैं। साबुत अनाज, दालें,हरी सब्जियाँ,फल,कम वसा वाला दूध,दही और पर्याप्त प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा मानसिक क्षमता को भी बढ़ाते हैं।

चालीस और पचास वर्ष की आयु के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है। इस समय मधुमेह, उच्च रक्तचाप,हृदय रोग और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए भोजन की मात्रा पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। अधिक फाइबर वाले खाद्य पदार्थ जैसे ओट्स,साबुत अनाज,फल और हरी सब्जियाँ पाचन को बेहतर बनाते हैं और वजन नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। नमक,चीनी और तले हुए भोजन का सेवन सीमित करना चाहिए।

वृद्धावस्था में शरीर की मांसपेशियाँ कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है और पाचन क्षमता भी घट सकती है। इस अवस्था में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी12 और ओमेगा-3 फैटी एसिड का पर्याप्त सेवन अत्यंत आवश्यक है। दूध,पनीर,दालें,मछली, मेवे,बीज और हरी पत्तेदार सब्जियाँ शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं। साथ ही पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी है क्योंकि बढ़ती उम्र में प्यास का एहसास कम हो सकता है।

हालाँकि हर उम्र की अपनी अलग पोषण संबंधी आवश्यकताएँ होती हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। प्रतिदिन रंग-बिरंगे फल और सब्जियाँ खाएँ,साबुत अनाज को प्राथमिकता दें, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें,चीनी और नमक का सीमित उपयोग करें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार मिलकर बेहतर स्वास्थ्य की आधारशिला बनाते हैं।

आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली में त्वरित और स्वादिष्ट भोजन का आकर्षण बढ़ गया है,लेकिन स्वास्थ्य की कीमत पर सुविधा का चुनाव बुद्धिमानी नहीं है। घर का ताजा भोजन,भोजन के लेबल पढ़ने की आदत और सोच-समझकर खाना खाने की संस्कृति हमें अनेक बीमारियों से बचा सकती है।

उम्र के अनुसार खाइए कोई फैशन या नया डाइट ट्रेंड नहीं है, बल्कि विज्ञान पर आधारित जीवनशैली है। हमारा शरीर हर उम्र में अलग तरह से काम करता है और उसे उसी के अनुरूप पोषण चाहिए। यदि हम अपनी उम्र के अनुसार सही भोजन चुनें, तो न केवल बीमारियों से बच सकते हैं बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर बना सकते हैं।

भोले का सावन

कार्तिकेय कुमार त्रिपाठी राम
इन्दौर, मध्यप्रदेश

इधर-उधर क्यूं जाते भोले,
पास मेरे तुम आओ ना,
सावन की ये बेला आई,
आकर तुम मुस्काओ ना।
इधर-उधर क्यूं ...
झूम-झूमकर बादल आया,
धरा होले से फिर मुस्काई,
अंबुआ के पेड़ों पर देखो,
झूलों ने फिर ली अंगड़ाई।
इधर-उधर क्यूं ...
बेल की डाली का पत्ता भी,
क्या-क्या है मुझसे बोला,
भोले से जब मिलकर आया,
प्रेम का रस उसने घोला।
इधर-उधर क्यूं ...
मोंगर और केवड़ नें अपनी,
खुशबू चहुं और बिखराई,
भोले ने आकर फिर सबको,
अपनी मोहक छवि दिखलाई।
इधर-उधर क्यूं ...
सावन होता है मनभावन,
भोले भक्ति से मन हो पावन,
जगर-मगर हो जाए जीवन,
जब आए भोले का सावन।
इधर-उधर क्यूं....

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

क्या लापरवाही बन गई कार्यशैली? हाईकोर्ट की नाराजगी,सत्र न्यायालय का जुर्माना और स्थानांतरण के बाद भी कोरिया में मौजूदगी पर सवाल

एक विवेचक...दो न्यायालय...और कई अनुत्तरित सवालों के घेरे में विनोद पासवान

- हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब,सत्र न्यायालय ने लगाया जुर्माना,स्थानांतरण के बाद भी कोरिया में मौजूदगी पर चर्चा
- न्यायालयों की नाराजगी के केंद्र में एक ही विवेचक, हाईकोर्ट की सख्ती,सत्र न्यायालय का अर्थदंड और फिर भी नहीं छोड़ा कोरिया जिला
- गवाही में गैरहाजिरी,न्यायालय की फटकार और स्थानांतरण के बाद भी डटे निरीक्षक,विनोद पासवान पर उठे कई सवाल, जवाब का इंतजार
- कोर्ट की फटकार से स्थानांतरण तक...आखिर क्यों चर्चा में हैं निरीक्षक विनोद पासवान ?
- कोरिया से नारायणपुर तबादला,फिर भी नहीं छोड़ा जिला!

-न्यूज डेस्क-

कोरिया/रामानुजगंज/बिलासपुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

पुलिस विभाग में विवेचक (जांच अधिकारी) की भूमिका किसी भी आपराधिक मुकदमे की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है,एक विवेचक की सक्रियता और समयबद्ध कार्यवाही से न केवल अपराध की जांच प्रभावित होती है, बल्कि न्यायालय में मुकदमे के निष्पादन की गति भी उसी पर निर्भर करती है,लेकिन जब एक ही अधिकारी का नाम बार-बार न्यायालय की नाराजगी, लंबित गवाही,प्रशासनिक सवालों और चर्चित मामलों से जुड़ने लगे,तब मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। कोरिया जिले में पदस्थ रहे निरीक्षक विनोद पासवान इन दिनों ठीक ऐसे ही कारणों से चर्चा में हैं,बीते कुछ दिनों के भीतर दो अलग-अलग न्यायालयों की टिप्पणियों ने उनकी कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं, एक ओर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को एनडीपीएस के एक मामले में विवेचक की अनुपस्थिति पर सीधे पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से व्यक्तिगत शपथपत्र तलब करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर रामानुजगंज सत्र न्यायालय ने लगातार गवाही के लिए अनुपस्थित रहने और न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध 500 रुपये का अर्थदंड लगाया,अब इन दोनों घटनाक्रमों के बीच उनका स्थानांतरण और उसके बाद भी कोरिया जिले में बने रहने की चर्चा ने कई नए सवाल पैदा कर दिए हैं।

अब स्थानांतरण पर भी उठ रहे सवाल- इसी बीच पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में क्रमांक 51 पर निरीक्षक विनोद पासवान का जिला कोरिया से जिला नारायणपुर स्थानांतरण किया गया है,कार्यालयीन सूत्रों के अनुसार उन्हें 11 जुलाई 2026 को कोरिया जिले से कार्यमुक्त (रिलीव) भी कर दिया गया था, हालांकि इस संबंध में रिलीविंग आदेश की प्रति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हो सकी है और पुलिस विभाग की ओर से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, यदि सूत्रों की जानकारी सही है,तो कई प्रशासनिक प्रश्न खड़े होते हैं कार्यमुक्त होने के बाद भी वे कोरिया जिले में किस आदेश के तहत कार्य कर रहे हैं? क्या उन्हें किसी विशेष विवेचना के लिए रोका गया है? यदि हां,तो क्या इसका कोई लिखित आदेश है? यदि नहीं, तो स्थानांतरण आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं हुआ?

क्या सीबीआई जांच वजह है?- स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि वे कुछ महत्वपूर्ण मामलों के कारण अभी भी कोरिया में हैं, हालांकि इस संबंध में न तो सीबीआई और न ही पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है,इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी जांच एजेंसी का कार्य किसी एक अधिकारी पर निर्भर है,यदि वास्तव में किसी प्रशासनिक या जांच संबंधी कारण से उन्हें रोका गया है,तो इसका आधिकारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक अटकलों पर विराम लग सके।

दो न्यायालयों की टिप्पणी,एक अधिकारी पर बढ़ते सवाल- महज कुछ दिनों के भीतर दो अलग-अलग न्यायालयों की कार्यवाही ने एक ही अधिकारी की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं,एक मामले में हाईकोर्ट को डीजीपी से व्यक्तिगत शपथपत्र मांगना पड़ा, दूसरे मामले में सत्र न्यायालय ने अर्थदंड लगाकर वेतन से राशि काटने का आदेश दिया,इन दोनों घटनाओं ने पुलिस विभाग में विवेचकों की जवाबदेही और न्यायालय के प्रति उत्तरदायित्व पर नई बहस छेड़ दी है।

सबसे बड़ा सवाल पुलिस विभाग से- यदि एक अधिकारी के संबंध में न्यायालय को बार-बार हस्तक्षेप करना पड़े,गवाही के लिए अनुपस्थिति पर डीजीपी से जवाब मांगना पड़े, दूसरे न्यायालय को आर्थिक दंड लगाना पड़े,और स्थानांतरण के बाद भी उसकी मौजूदगी पर सवाल उठने लगें,तो यह केवल व्यक्तिगत कार्यशैली का मामला नहीं रह जाता,यह प्रशासनिक निगरानी, जवाबदेही और अनुशासन की व्यवस्था पर भी प्रश्न खड़ा करता है,अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस मुख्यालय और कोरिया पुलिस इन घटनाक्रमों को केवल एक सामान्य प्रशासनिक प्रकरण मानते हैं या फिर पूरे मामले की विभागीय समीक्षा कर यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायालयों की टिप्पणियों के बाद क्या जवाबदेही तय की गई और स्थानांतरण आदेश के बावजूद संबंधित अधिकारी की वर्तमान स्थिति क्या है।

पहला मामला : विवेचक नहीं पहुंचे तो हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा जवाब

कोरिया जिले के पटना थाना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में आरोपी अभिषेक सारथी उर्फ बाबू सितंबर 2024 से जेल में बंद है। मुकदमे की सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी, अभियोजन के 13 गवाहों में से 12 के बयान दर्ज हो चुके थे, लेकिन विवेचक का बयान शेष था। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि विवेचक ट्रायल कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे, जिससे सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी, मामले को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2026 को डीजीपी से व्यक्तिगत शपथपत्र तलब किया, इसके बाद पुलिस अधीक्षक, कोरिया द्वारा संबंधित विवेचक से स्पष्टीकरण मांगा गया और 29 जुलाई को उन्हें ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत कर उनका बयान दर्ज कराया गया, हालांकि हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आरोपी से बरामद मादक पदार्थ व्यावसायिक मात्रा से अधिक है, लेकिन आदेश में विवेचक की अनुपस्थिति और उसके बाद हुई कार्रवाई स्पष्ट रूप से दर्ज है।

दूसरा मामला : सत्र न्यायालय ने लगाया अर्थदंड

हाईकोर्ट का मामला अभी चर्चा में ही था कि रामानुजगंज सत्र न्यायालय ने भी निरीक्षक विनोद पासवान के खिलाफ सख्त आदेश पारित कर दिया, सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने एम.जे.सी. (क्रि.) क्रमांक 41/2026 में पाया कि विभिन्न सत्र प्रकरणों में समन,जमानतीय वारंट और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बावजूद संबंधित अधिकारी गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, तत्कालीन उपनिरीक्षक विनोद पासवान ने न्यायालय में उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण दिया कि वे थाना सोनहत के एक मामले की विवेचना तथा सीबीआई को केस डायरी सौंपने की प्रक्रिया में व्यस्त थे और इसी कारण न्यायालय नहीं पहुंच सके। उन्होंने अपनी त्रुटि के लिए क्षमा भी मांगी,लेकिन न्यायालय ने यह स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया,आदेश में उल्लेख किया गया कि उन्हें समन विधिवत तामील कराया गया था तथा बाद में जमानतीय वारंट भी जारी किया गया, फिर भी वे पूर्व सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहे,जिससे न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हुई, इसी आधार पर न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 389 के तहत 500 रुपये का अर्थदंड लगाया तथा कोरिया पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि उक्त राशि अधिकारी के वेतन से काटकर न्यायालय में जमा कराई जाए।

लगातार विवादों में रहा कार्यकाल

यह पहला अवसर नहीं है जब निरीक्षक विनोद पासवान का नाम विवादों के साथ सामने आया हो, कोरिया जिले में उनके कार्यकाल के दौरान कई संवेदनशील मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे,पटना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग द्वारा थाना से जाने के बाद आत्महत्या का मामला हो या फिर सोनहत थाना क्षेत्र का चर्चित नौगई तिहरा हत्याकांड,इन मामलों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर पुलिस की भूमिका और विवेचना को लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं,इन मामलों में विभिन्न स्तरों पर सवाल उठे हैं,हालांकि उन पर न्यायालय द्वारा इस समाचार में वर्णित मामलों जैसी कोई टिप्पणी इस रिपोर्ट के आधार पर उपलब्ध नहीं है।

स्मार्ट मीटर पर कांग्रेस ने चिपकाए 'महतारी वंदन वसूली मीटर' के स्टीकर,घर-घर पहुंचकर भरवाए विरोध के फॉर्म

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने अपना प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के नेतृत्व में शहर के गोधनपुर मोहल्ले और ग्राम मेन्द्राकला में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर लोगों से स्मार्ट मीटर के विरोध में तैयार मांग-पत्र पर हस्ताक्षर कराए और जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगे हैं,वहां 'महतारी वंदन वसूली मीटर' लिखे स्टीकर चिपकाए। प्रदेश कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में दो माह तक आंदोलन चलाने की घोषणा की है। इसी के तहत 1 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों में प्रेसवार्ता कर आंदोलन की रूपरेखा जारी की गई थी। सरगुजा में अब इसकी शुरुआत जनसंपर्क अभियान से की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता उपभोक्ताओं से हस्ताक्षर कराकर सरकार से स्मार्ट मीटर हटाने, बिजली दरों में की गई वृद्धि वापस लेने और पूर्व की बिजली बिल हाफ योजना को दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने कहा कि भाजपा सरकार महतारी वंदन योजना के नाम पर महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का प्रचार कर रही है, लेकिन स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों के जरिए आम लोगों से उससे अधिक राशि वसूली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक हाथ से सहायता देती है और दूसरे हाथ से बिजली बिल के माध्यम से उसे वापस ले लेती है। इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटरों पर 'महतारी वंदन वसूली मीटर' के स्टीकर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में उपभोक्ता मांग-पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिससे स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर जनता की नाराजगी साफ दिखाई देती है। अभियान में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता,अंबिकापुर ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनय शर्मा,मंडल अध्यक्ष अमित सिन्हा, मिथुन सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

राजीव भवन में मनाई गई पं. रविशंकर शुक्ल और पं. विद्याचरण शुक्ल की जयंती,कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा द्वारा रविवार को राजीव भवन में अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित विद्याचरण शुक्ल की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दोनों दिवंगत नेताओं के चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनके सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक योगदान और जनसेवा को याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि पंडित रविशंकर शुक्ल आधुनिक मध्यप्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी और शिक्षा, सिंचाई, प्रशासन तथा आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कीं। उन्होंने कहा कि उनका पूरा जीवन जनसेवा, सादगी और विकास के प्रति समर्पित रहा, जिससे आज भी नई पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित विद्याचरण शुक्ल के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का प्रभावी प्रतिनिधित्व किया। लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास और जनहित के मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी। उनका व्यक्तित्व कुशल संगठनकर्ता, प्रभावशाली वक्ता और जननेता के रूप में जाना जाता है। उनके कार्य आज भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बालकृष्ण पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में ऐसे नेताओं के आदर्शों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, जिन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और जनहित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दोनों दिवंगत नेताओं के आदर्शों का अनुसरण करते हुए समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने का संकल्प लिया।

बारिश से बचने पेड़ के नीचे रुके दंपती पर गिरी बिजली,पति की मौत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रकेली में खेत में रोपाई के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। घायल महिला का अंबिकापुर के निजी अस्पताल में उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार रकेली निवासी बिहारी मिंज जो शासकीय स्कूल में प्यून के पद पर कार्यरत था, शनिवार शाम करीब 4 बजे अपनी पत्नी सोनमेत मिंज के साथ खेत में धान की रोपाई करने गया था। इसी दौरान हल्की बारिश शुरू होने पर दोनों बचाव के लिए खेत के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण दोनों को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। जांच के बाद चिकित्सकों ने बिहारी मिंज को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनकी पत्नी सोनमेत मिंज को गंभीर हालत में अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है।

प्रतिबंध के 48 घंटे के भीतर कार्रवाई: बस से पकड़ा गया 'एनालॉग पनीर', अब सीमाओं पर भी रहेगी नजर

सरगुजा में खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान शुरू,राजहंस ट्रेवल्स की बस से जब्त हुआ प्रतिबंधित पनीर...कारोबारियों को चेतावनी...बिना बिल मिला तो होगी सख्त कार्रवाई

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

राज्य सरकार द्वारा एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने के दो दिन के भीतर सरगुजा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रविवार तड़के नए बस स्टैंड पर चलाए गए विशेष जांच अभियान में राजहंस ट्रेवल्स की एक बस से प्रतिबंधित श्रेणी का एनालॉग पनीर जब्त किया गया। मामले में अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राज्य शासन ने 31 जुलाई को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में अमानकीकृत डेयरी एनालॉग (एनालॉग पनीर) और अन्य ऐसे खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण व बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। इसके बाद सरगुजा जिले में विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया गया। रविवार सुबह करीब पांच बजे खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम नए बस स्टैंड पहुंची और

बसों समेत अन्य वाहनों की जांच की। इसी दौरान राजहंस ट्रेवल्स की बस (CG 15 EC 0828) से प्रतिबंधित पनीर का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। टीम ने सामग्री जब्त कर मामला दर्ज किया।

अब केवल बस स्टैंड नहीं,जिले की सीमाओं पर भी सख्ती : विभाग के अनुसार अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिले में प्रवेश करने वाले प्रमुख मार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों,बसों,मालवाहक वाहनों और अन्य परिवहन साधनों की नियमित व आकस्मिक जांच की जाएगी ताकि प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की आवाजाही पूरी तरह रोकी जा सके।

व्यापारियों को साफ चेतावनी : खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने डेयरी उत्पादों के थोक और खुदरा कारोबारियों को नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि बिना वैध स्रोत,खरीद बिल और आपूर्तिकर्ता की जानकारी के किसी भी पनीर या दुग्ध उत्पाद की खरीद-बिक्री न करें। नियमों के उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बस संचालकों और ट्रांसपोर्टरों को भी चेताया गया है कि प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के परिवहन में सहयोग करने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी।

भास्कर एंगल 7 सवाल जो जवाब मांगते हैं

कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ है,लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल अब भी बने हुए हैं...

- जब्त किए गए एनालॉग पनीर की कुल मात्रा कितनी थी?
- यह कहां से लाया जा रहा था और किसके लिए भेजा गया था?
- क्या यह पहली खेप थी या पहले भी इसी तरह परिवहन होता रहा?
- जिले के होटल,ढाबों,रेस्टोरेंट और फास्ट फूड सेंटरों में पहले से उपयोग हो रहे संदिग्ध पनीर की जांच कब होगी?
- केवल परिवहन पर कार्रवाई पर्याप्त होगी या आपूर्ति श्रृंखला और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक भी जांच पहुंचेगी?

खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंध तभी प्रभावी होगा जब परिवहन के साथ-साथ बाजार,गोदाम,होटल और डेयरी प्रतिष्ठानों की लगातार जांच हो तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सार्वजनिक की जाए।

श्रावण का शुभारंभ,शिवमय हुआ कोरिया-एमसीबी का वनांचल

सीतामढ़ी से नीलकंठ और हसदेवेश्वर तक उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब...

सावन में शिवभक्ति का महासंगम प्राकृतिक गुफाओं,पर्वत शिखरों और प्राचीन शिवधामों में उमड़ रही आस्था

घने जंगल, ऊंचे पर्वत और 'हर-हर महादेव' के जयघोष...शिवमय होगा पूरा वनांचल

नीलकंठ, जटाशंकर, सीतामढ़ी और हसदेवेश्वर धाम में उमड़े श्रद्धालु

जहां प्रकृति भी करती है शिव की आराधना...श्रावण मास में नीलकंठ, जटाशंकर,सीतामढ़ी और

विहंगम वादियों में विराजे नीलकंठ महादेव, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे प्राचीन शिवधाम,सीतामढ़ी से सिद्ध बाबा तक उमड़ा आस्था का सैलाब

राजन पाण्डेय

सोनहत/कोरिया,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

देवों के देव महादेव की आराधना का सबसे पावन महीना श्रावण मास प्रारंभ होते ही कोरिया और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) अंचल का पूरा वनांचल शिवमय हो उठा है, घने साल और सागौन के जंगल,बादलों को छूती पर्वत श्रृंखलाएं,कल-कल बहती जलधाराएं और प्रकृति की गोद में बसे प्राचीन शिवधाम इन दिनों श्रद्धा और आस्था के अद्भुत संगम के साक्षी बन रहे हैं,'हर-हर महादेव ','बोल बम' और'? नमः शिवाय' के जयघोष से वातावरण भक्तिमय हो गया है,श्रावण मास के प्रथम दिन से ही हजारों श्रद्धालु कांवड़ में पवित्र जल भरकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए विभिन्न शिवधामों की ओर पैदल यात्रा कर रहे हैं,कोरिया रियासतकालीन इतिहास, रामायणकालीन मान्यताओं और प्राकृतिक गुफाओं में विराजमान स्वयंभू शिवलिंगों के कारण यह पूरा क्षेत्र धार्मिक पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है।

सावन का महत्व : शिव आराधना का सबसे पवित्र काल- सनातन परंपरा में श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, मान्यता है कि इसी महीने भगवान शिव की आराधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है, प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा-अर्चना,रुद्राभिषेक और जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है, कोरिया और एमसीबी जिले के प्राचीन शिवधामों में इस दौरान हजारों श्रद्धालु दूर-दूर से पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश के अनूपपुर,शहडोल,सीधी,उमरिया और आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं।

सीतामढ़ी धाम : जहां गुफा के गर्भ में विराजमान हैं स्वयंभू महादेव

सोनहत विकासखंड के समीप घने जंगलों के बीच स्थित सीतामढ़ी धाम पूरे क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है, कोरिया रियासतकाल में खोजे गए इस पवित्र स्थल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशाल प्राकृतिक गुफा है, गुफा के भीतर स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, जहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को अत्यंत संकरे मार्ग से घुटनों के बल रेंगकर जाना पड़ता है, भीतर पहुंचते ही प्राकृतिक चट्टानों के बीच टिमटिमाते दीपक और जल की बूंदों से निर्मित वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है, स्थानीय मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं, सावन में यहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं।

जटाशंकर धाम : कठिन रास्ता,लेकिन अटूट श्रद्धा

घनघोर जंगलों के बीच स्थित जटाशंकर धाम अपनी प्राकृतिक गुफा और दुर्गम यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है,करीब 21 हाथ लंबी संकरी प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थापित शिवलिंग तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु घुटनों के बल आगे बढ़ते हैं,वर्षों से यहां संत रामेश्वर प्रसाद दास बाबा एकांत साधना कर रहे हैं, उनका आश्रम भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है,सावन के दौरान यहां दिनभर 'बोल बम' के जयघोष गूंजते रहते हैं और श्रद्धालु प्राकृतिक जलधाराओं का जल चढ़ाकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

नीलकंठ महादेवः बादलों के बीच शिव का अद्भुत धाम- यदि प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम देखना हो तो नीलकंठ महादेव से बेहतर स्थान शायद ही कोई हो, सोनहत मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की पर्वत श्रृंखलाओं के सर्वोच्च शिखर पर स्थित यह प्राचीन शिवधाम श्रद्धालुओं के लिए किसी तपोभूमि से कम नहीं है, ऊंची पहाड़ी पर पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही श्रद्धालु शिखर पर पहुंचते हैं, चारों ओर फैली हरियाली, बादलों से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं और दूर-दूर तक फैला वनांचल मन को अलौकिक शांति से भर देता है, सावन में यहां स्थानीय समितियों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पेयजल और विश्राम की विशेष व्यवस्था की जाती है।

हसदेवेश्वर महादेवः जहां से निकलती है जीवनदायिनी हसदो नदी

सोनहत विकासखंड के मेंड्रा गांव में स्थित हसदेवेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है,यह मंदिर हसदो नदी के उद्गम स्थल के सामने स्थित है, पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. चरण दास महंत के प्रयासों से निर्मित यह भव्य मंदिर अब पूरे क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है,श्रद्धालु हसदो नदी के उद्गम से जल भरकर भगवान हसदेवेश्वर का जलाभिषेक करते हैं, पूरे सावन माह यहां रुद्राभिषेक,महामृत्युंजय जाप,भजन-कीर्तन और विशाल भंडारों का आयोजन होता है।

सिद्ध बाबा पहाड़ : आस्था और पर्यटन का उभरता केंद्र

राष्ट्रीय राजमार्ग-43 से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व का अनूठा संगम है,पहाड़ी की चोटी पर स्थित प्राचीन शिवलिंग वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा है,यहां वर्तमान में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर विशाल शिव मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है,स्थानीय लोगों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यह स्थल छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्रों में अपनी अलग पहचान बनाएगा।

शिवगुफा,शिवघाट और देवगढ़ : जहां इतिहास भी बोलता है- ग्राम कछार स्थित शिवगुफा एवं शिवघाट प्राकृतिक शिव साधना के प्राचीन केंद्र हैं,श्रद्धालु हसदो नदी से जल भरकर प्राकृतिक गुफा में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं,वहीं देवगढ़ (चामट पहाड़) में लगभग दो दशक पहले वन विभाग की खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां और मंदिर के अवशेष मिले थे,इसके बाद यहां ग्रामीणों ने बाबा चौरसिया की स्थापना कर मंदिर का निर्माण कराया। आज यह भी सावन में श्रद्धालुओं का प्रमुख आस्था केंद्र बन चुका है।

रामायणकालीन मान्यता से जुड़ा घघरा शिव मंदिर- भरतपुर विकासखंड के घघरा गांव स्थित शिव मंदिर को लेकर स्थानीय मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने वनवास काल में यहां शिवलिंग की स्थापना की थी। यही कारण है कि इस मंदिर का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है।

कांवड़ यात्रा से गूंज रहे जंगलों के रास्ते- सावन के दौरान श्रद्धालु नदियों, झरनों और पवित्र जलस्रोतों से जल भरकर कई किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं,रास्ते भर 'बोल बम ','हर-हर महादेव' और'? नमः शिवाय' के उद्घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं,जहां श्रद्धालुओं के लिए पेयजल,चिकित्सा,प्रसाद और विश्राम की व्यवस्था की गई है।

प्राकृतिक पर्यटन को भी मिल रही नई पहचान- धार्मिक महत्व के साथ-साथ ये सभी स्थल प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं,नीलकंठ महादेव की पहाड़ियां, सीतामढ़ी और जटाशंकर की गुफाएं, हसदो नदी का उद्गम,सिद्ध बाबा की पहाड़ी और देवगढ़ की ऐतिहासिक धरोहरें हर वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं,यदि इन स्थलों का योजनाबद्ध विकास किया जाए तो कोरिया और एमसीबी जिला धार्मिक पर्यटन के राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना सकता है।

श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की अपील-

प्रशासन और मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि दर्शन के दौरान स्वच्छता बनाए रखें,प्लास्टिक का उपयोग न करें, जंगलों में आग से बचाव करें तथा निर्धारित मार्गों का ही उपयोग करें,ताकि धार्मिक आस्था के साथ प्राकृतिक धरोहर भी सुरक्षित रह सके।

शिव केवल आराध्य नहीं, जीवन का दर्शन हैं...

श्रावण मास केवल पूजा-पाठ और जलाभिषेक का पर्व नहीं है, यह आत्मसंयम, सेवा, करुणा, त्याग और लोककल्याण का संदेश देने वाला आध्यात्मिक महापर्व है, भगवान शिव का नीलकंठ स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन की विषमताओं और कटु अनुभवों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करते हुए भी समाज के लिए सकारात्मक बने रहना ही सच्चा शिवत्व है, उनका त्रिशूल संतुलन और न्याय का, डमरू सृजन का, जटाओं से बहती गंगा पवित्रता का और नंदी अटूट श्रद्धा एवं सेवा का प्रतीक है, सावन हमें केवल मंदिरों तक नहीं बुलाता, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता का त्याग कर सत्य, सादगी, सद्भाव और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है, कोरिया और एमसीबी का यह वनांचल हर सावन में केवल 'हर-हर महादेव' के जयघोष से ही नहीं गूंजता, बल्कि प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और अध्यात्म के अद्भुत समन्वय का जीवंत उदाहरण बनकर श्रद्धालुओं को जीवन का गहरा संदेश भी देता है।

गांधी चौक पर बड़ा हादसा टला, बस की टक्कर के बाद 15 मीटर तक घिसटती रही स्कूटी

स्कूटी सवार युवक सड़क पर गिरा,लोगों के शोर मचाने पर रुकी बस,घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शहर के व्यस्त गांधी चौक पर रविवार दोपहर एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। यात्रियों से भरी एक बस ने स्कूटी सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद युवक सड़क पर गिर गया, जबकि उसकी स्कूटी बस में फंस गई और करीब 15 मीटर तक घिसटती चली गई। लोगों के शोर मचाने पर चालक ने बस रोकी। हादसे में युवक घायल हो गया, जबकि स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार छाबड़ा बस प्रतीक्षा बस स्टैंड से यात्रियों को लेकर जा रही थी। गांधी चौक के पास पहुंचते ही बस ने सामने चल रही

स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक स्कूटी से उछलकर सड़क पर गिर गया और घिसटने से उसके चेहरे सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आईं। वहीं स्कूटी बस में फंस गई और चालक उसे करीब 15 मीटर तक घसीटता ले गया। घटना के दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर बस रुकवाई। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। हादसे के बाद कुछ देर तक गांधी चौक पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने बस को मौके पर रोककर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

गांधी चौक बना हादसों का हॉटस्पॉट

स्थानीय लोगों का कहना है कि गांधी चौक पर लगातार बढ़ते यातायात और अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने यहां प्रभावी यातायात व्यवस्था और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है।

अंडा नहीं मिला तो 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक

लखनपुर के जमगला गांव की घटना,पुलिस व ग्रामीणों की समझाइश के बाद सुरक्षित उतारा गया नीचे,मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जमगला में रविवार को एक युवक अंडा नहीं मिलने से नाराज होकर करीब 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर की ऊंचाई पर खड़ा देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार ग्राम जमगला निवासी शिवशंकर (20-25 वर्ष), पिता सुकुल को रोज अंडा खाने की आदत थी। रविवार सुबह उसे अंडा नहीं मिला तो वह नाराज होकर गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ते देख परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा लगातार उसे नीचे उतरने की समझाइश देते रहे,लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लखनपुर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझाया और भरोसा दिलाया कि उसे अंडा खाने के लिए दिया जाएगा। परिजनों और ग्रामीणों ने भी उसे सुरक्षित नीचे उतरने के लिए मनाया। काफी देर की मशक्कत के बाद युवक टावर से नीचे उतर आया,जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। घटना के दौरान गांव में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक कौतूहल का माहौल बना रहा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक की मानसिक स्थिति कुछ समय से सामान्य नहीं बताई जा रही है। पुलिस ने उसे सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

कृष्णा जायसवाल का निधन,बैकुंठपुर मुक्तिधाम में हुआ अंतिम संस्कार

बैकुंठपुर (कोरिया),02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

अजय इलेक्ट्रिकल बैकुंठपुर के संचालक दिनेश जायसवाल की माताजी एवं अजय मेडिकल स्टोर के संचालक की भाभी श्रीमती कृष्णा जायसवाल का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अजय जायसवाल (अजय मेडिकल स्टोर) के संचालक की भाभी श्रीमती कृष्णा जायसवाल के निधन का समाचार मिलते ही परिजनों, शुभचिंतकों एवं नगरवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। रविवार को बैकुंठपुर स्थित मुक्तिधाम में पूरे धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में परिजन, रिश्तेदार, मित्र एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

आजीवन प्रतिनियुक्ति के ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा?

कोरिया कलेक्ट्रेट का 'फेविकोल मॉडल'!

- 12 दस्तावेजी खुलासे...
- 24 साल की प्रतिनियुक्ति...
- फिर भी शासन मौन!

"दूध का दूध, पानी का पानी" कब होगा?

खबरें गलत थीं तो खंडन क्यों नहीं?
सही थीं तो जांच और कार्रवाई क्यों नहीं?

24 साल की प्रतिनियुक्ति का अंत कब? आजीवन व्यवस्था बनी तो ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा?

12 दस्तावेजी खुलासे...24 साल की प्रतिनियुक्ति...फिर भी शासन मौन! आखिर ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा?

-रवि सिंह-
बैकुण्ठपुर/कोरिया,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कहावत है- 'सांच को आंच नहीं'। यदि कोई आरोप या सवाल निराधार है तो उसका सबसे सशक्त उत्तर तथ्यों और दस्तावेजों के साथ दिया जाता है,लेकिन यदि सवाल लगातार उठते रहें, दस्तावेज सामने आते रहें और शासन-प्रशासन की ओर से केवल सन्नाटा सुनाई दे,तो स्वाभाविक है कि सवाल और गहरे होते चले जाएं। कोरिया कलेक्टरेट का चर्चित स्टेनो टू कलेक्टर प्रतिनियुक्ति प्रकरण अब किसी एक कर्मचारी की सेवा यात्रा का मामला भर नहीं रह गया है। यह मामला अब प्रशासनिक जवाबदेही, सेवा नियमों की विश्वसनीयता, प्रतिनियुक्ति व्यवस्था की पारदर्शिता और शासन की संवेदनशीलता की परीक्षा बन चुका है, दैनिक घटती-घटना इस पूरे मामले पर लगातार 12 दस्तावेज आधारित समाचार प्रकाशित कर चुका है ये 13 वां समाचार प्रकाशित हो रहा है, इन समाचारों में प्रतिनियुक्ति आदेश, मत्स्य महासंघ के पत्र,सेवा पुस्तिका,वेतन निर्धारण, सेवा निरंतरता, संविलियन के प्रयास,विभागीय पत्राचार तथा अन्य प्रशासनिक अभिलेखों के आधार पर कई गंभीर प्रश्न उठाए गए, लेकिन इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद भी न तो किसी तथ्य का विस्तृत आधिकारिक खंडन सामने आया,न सार्वजनिक रूप से किसी जांच की जानकारी दी गई और न ही संबंधित विभागों ने क्रमवार स्थिति स्पष्ट की,अब सवाल किसी व्यक्ति पर नहीं,बल्कि शासन की प्रतिक्रिया पर खड़ा हो गया है।

आजीवन प्रतिनियुक्ति के ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा?

कोरिया जिले में वर्षों से चर्चा का विषय बनी यह प्रतिनियुक्ति आखिर कब समाप्त होगी? क्या यह प्रतिनियुक्ति भी एक दिन अपने नियमानुसार समाप्त होकर संबंधित कर्मचारी की मूल विभाग में वापसी के साथ खत्म होगी,या फिर इसे प्रशासनिक इतिहास में 'आजीवन प्रतिनियुक्ति' के एक नए मॉडल के रूप में दर्ज किया जाएगा? उपलब्ध दस्तावेजों और वर्षों से उठ रहे सवालों के बीच अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि प्रतिनियुक्ति एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है, तो इसका स्वाभाविक अंत कब होगा? क्या संबंधित विभाग स्वयं इसे समाप्त कर कर्मचारी को उसके मूल विभाग में वापस भेजेगा,या यह व्यवस्था बिना किसी स्पष्ट निर्णय के अनिश्चितकाल तक चलती रहेगी? प्रशासनिक गलियारों में अब व्यंग्य के साथ यह चर्चा भी सुनाई देने लगी है कि 'आजीवन प्रतिनियुक्ति के ताबूत में आखिरी कील आखिर कौन ठोकेगा?' क्या यह कील सेवा नियम ठोकेंगे, सक्षम प्राधिकारी ठोकेंगे,विभागीय समीक्षा ठोकेगी, या फिर यह प्रतिनियुक्ति कभी समाप्त ही नहीं होगी और प्रशासनिक फाइलों में हमेशा के लिए बंद होकर रह जाएगी? लोकतंत्र में किसी भी प्रतिनियुक्ति का उद्देश्य व्यवस्था को चलाना होता है,न कि उसे स्थायी परंपरा बना देना। इसलिए अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या वर्षों से चल रही इस व्यवस्था का नियमानुसार समापन होगा और यदि होगा,तो वह निर्णय आखिर कौन करेगा? यही प्रश्न आज पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनकर सामने खड़ा है।

मत्स्य विभाग का कर्मचारी...लेकिन पहचान राजस्व विभाग की-उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रश्न उठता है कि संबंधित कर्मचारी का मूल संबंध मत्स्य विभाग/मत्स्य महासंघ से रहा, इसके बावजूद वर्षों तक वह कलेक्टर कार्यालय में स्टेनो टू कलेक्टर के रूप में कार्यरत रहे, अब कई प्रशासनिक प्रश्न सामने हैं–यदि मूल विभाग मत्स्य था, तो राजस्व विभाग में इतनी लंबी अवधि तक सेवा किस नियम के तहत जारी रही? यदि संविलियन हुआ,तो उसका स्पष्ट आदेश कहां है? यदि संविलियन नहीं हुआ, तो प्रतिनियुक्ति समाप्त क्यों नहीं हुई? यदि प्रतिनियुक्ति जारी रही, तो उसका समय-समय पर नवीनीकरण किन आदेशों से हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर केवल सक्षम विभाग ही दे सकता है।

जब शासन मौन हो जाए...तो सवाल और बुलंद हो जाते हैं...

लोकतंत्र में पत्रकारिता का दायित्व प्रश्न पूछना है और शासन का दायित्व तथ्यों के आधार पर उत्तर देना,यदि कोई समाचार तथ्यात्मक रूप से गलत है तो उसका खंडन करना शासन के लिए कठिन नहीं होता,यदि किसी मामले में प्रथम दृष्टया जांच की आवश्यकता हो,तो जांच की घोषणा भी की जा सकती है, लेकिन इस प्रकरण में लगातार बारह समाचार प्रकाशित होने के बाद भी सार्वजनिक स्तर पर न खंडन सामने आया,न जांच की स्थिति स्पष्ट हुई और न ही रिकॉर्ड के आधार पर उठे प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर दिया गया,यह स्थिति स्वाभाविक रूप से जनचर्चा को जन्म देती है, लोग पूछ रहे हैं क्या खबरें गलत थीं? यदि गलत थीं तो आधिकारिक खंडन क्यों नहीं? यदि सही थीं तो जांच क्यों नहीं? यदि जांच हुई तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि शासन की विश्वसनीयता का आधार है।

प्रतिनियुक्ति या आजीवन व्यवस्था?

सरकारी सेवा नियमों में प्रतिनियुक्ति को अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था माना गया है,सामान्यतः इसकी अवधि तीन वर्ष होती है और विशेष परिस्थितियों में इसे सीमित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है,लेकिन इस पूरे प्रकरण में चर्चा तीन या पांच वर्ष की नहीं, बल्कि लगभग 24 वर्षों की हो रही है,यहीं से व्यंग्य जन्म लेता है, जिले में लोग कहते हैं- यह प्रतिनियुक्ति नहीं,स्थायी पता बन गई है, तो कोई मुस्कुराते हुए कहता है 'लगता है इस कुर्सी पर फेविकोल की ऐसी परत चढ़ी है कि समय भी उसे अलग नहीं कर पाया ',ये टिप्पणियां तथ्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक चुप्पी के बीच विकसित हुई जनचर्चा का हिस्सा हैं।

कलेक्टर बदलते रहे...लेकिन व्यवस्था नहीं बदली

पिछले दो दशकों में कोरिया जिले में अनेक कलेक्टर आए और गए,शासन बदला, प्रशासनिक प्राथमिकताएं बदलीं, लेकिन जिस व्यवस्था पर आज सवाल उठ रहे हैं,वह लगातार बनी रही,यही कारण है कि कर्मचारियों के बीच व्यंग्य में कहा जाने लगा— 'कलेक्टर का तबादला सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन स्टेनो की कुर्सी शायद स्थायी धरोहर है ',यह व्यंग्य इस बात का संकेत है कि लंबे समय तक किसी व्यवस्था पर उठते सवालों का उत्तर न मिले,तो सार्वजनिक धारणाएं बनना स्वाभाविक है।

सेवा पुस्तिका ने खोल दी पुरानी फाइल

जब मत्स्य महासंघ ने सेवा पुस्तिका और सेवा निरंतरता प्रमाण-पत्र की मांग की, तब यह पूरा मामला एक बार फिर चर्चा में आया, यहीं से प्रश्न उठा यदि कर्मचारी वर्षों से दूसरे विभाग में कार्यरत था, तो सेवा पुस्तिका का नियमित संधारण किसने किया? वार्षिक सत्यापन किस विभाग ने किया? क्या सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हुईं?

प्रतिनियुक्ति या स्थायी विरासत? आजीवन व्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा?

कलेक्टर बदलते रहे...सरकारें बदलती रहीं...लेकिन प्रतिनियुक्ति नहीं टूटी,आखिर ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा?

12 दस्तावेजी खुलासों के बाद भी शासन मौन, सवाल बरकरार—खबरें गलत थीं तो खंडन क्यों नहीं? सही थीं तो जांच और कार्रवाई कब?

12 दस्तावेजी खुलासे...24 साल की प्रतिनियुक्ति...फिर भी शासन मौन! आखिर यह चुप्पी किसकी हिफाजत कर रही है?

'दूध का दूध,पानी का पानी' कब होगा? खबरें गलत थीं तो खंडन क्यों नहीं? सही थीं तो जांच और कार्रवाई क्यों नहीं?

संविलियन हुआ या केवल प्रयास?-

दस्तावेज संकेत देते हैं कि राजस्व विभाग में संविलियन की दिशा में प्रयास हुए थे, लेकिन आज भी स्पष्ट प्रश्न मौजूद है यदि संविलियन हुआ तो आदेश कहां है? यदि नहीं हुआ, तो प्रतिनियुक्ति समाप्त क्यों नहीं हुई?

'फेविकोल मॉडल' की चर्चा क्यों?-

जिले में अब यह पूरा प्रकरण व्यंग्य का विषय भी बन गया है, कुछ लोग कहते हैं की यह प्रतिनियुक्ति नहीं, फेविकोल मॉडल है, एक बार कुर्सी मिली तो फिर वर्षों तक कोई हिला नहीं सकता, यह व्यंग्य प्रशासनिक चुप्पी से उपजी जनभावना का प्रतीक है, न कि किसी तथ्य का निष्कर्ष।

व्यवस्था कर्मचारी के लिए या कर्मचारी व्यवस्था के लिए?-

यह मामला अब केवल एक व्यक्ति का नहीं रह गया है, यह उन हजारों कर्मचारियों का भी प्रश्न है जो नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं और समय पूरा होने पर अपने मूल विभाग लौट आते हैं, यदि किसी मामले में अलग व्यवस्था अपनाई गई, तो उसका आधार भी सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में न्याय तभी दिखाई देता है जब नियम सभी पर समान रूप से लागू होते दिखाई दें।

आजीवन प्रतिनियुक्ति के ताबूत में आखिरी कील कौन ठोकेगा?-

अब इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है, क्या शासन स्वयं सामने आकर इस पूरे मामले का तथ्यात्मक उत्तर देगा? क्या संबंधित विभाग उपलब्ध दस्तावेजों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे? क्या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूरे प्रकरण की प्रशासनिक समीक्षा होगी? या फिर यह मामला भी वर्षों तक फाइलों में दबा रह जाएगा? कहावत है की सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, लोकतंत्र में सवाल पूछना पत्रकारिता का दायित्व है और उत्तर देना शासन की जिम्मेदारी, अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या कोरिया का यह चर्चित प्रतिनियुक्ति प्रकरण केवल एक कर्मचारी की सेवा कहानी बनकर रह जाएगा, या फिर प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही की ऐसी मिसाल बनेगा, जहां 'दूध का दूध और पानी का पानी' वास्तव में होकर रहेगा, और अंत में वही प्रश्न, जो अब पूरे प्रकरण का केंद्रीय प्रश्न बन चुका है—आजीवन प्रतिनियुक्ति के ताबूत में आखिरी कील आखिर कौन ठोकेगा?

सरगुजा संभाग की कमान नवीन जायसवाल को, प्रदेश संगठन ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

-संवाददाता-
प्रतापपुर/रायपुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्व अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के संगठन विस्तार अभियान के तहत सरगुजा संभाग की जिम्मेदारी नवीन जायसवाल को सौंप दी गई है। प्रदेश नेतृत्व द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार उन्हें सरगुजा संभाग का संभागीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद समाज के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और उन्हें लगातार बधाइयां एवं शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रदेश कार्यालय रायपुर से जारी नियुक्ति आदेश में बताया गया है कि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने,समाज को संगठित करने तथा अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के हितों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदेश में उल्लेख है कि प्रदेश स्तर पर समाज प्रमुखों एवं पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श और सर्वसम्मति के बाद यह निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ साहू की अनुशंसा पर जारी इस नियुक्ति आदेश के अनुसार नवीन जायसवाल से अपेक्षा की गई है कि वे सरगुजा संभाग में संगठन का विस्तार करेंगे, समाज के लोगों को एकजुट करेंगे तथा शिक्षा, सामाजिक जागरूकता,अधिकारों की रक्षा और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नियुक्ति की जानकारी सामने आने के बाद सरगुजा संभाग सहित विभिन्न जिलों के समाजजनों ने नवीन जायसवाल को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। समाज के लोगों ने कहा कि वे लंबे

समय से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का अनुभव रखते हैं। नवीन जायसवाल ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के प्रत्येक वर्ग को संगठन से जोड़ते हुए समाज के हितों,अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए मजबूती से कार्य किया जाए। साथ ही युवाओं को संगठन से जोड़कर सामाजिक एकता और विकास को नई गति देने की दिशा में भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। इस नियुक्ति को सरगुजा संभाग में संगठन विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि नवीन जायसवाल के नेतृत्व में संगठन और अधिक सक्रिय होकर समाज की उन्नति एवं जनहित के कार्यों को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएगा।

डीईओ का बड़ा एक्शन : 'व्यवस्था' के नाम पर चल रही पदस्थापना व्यवस्था खत्म

अब मूल संस्था में ही देनी होगी उपस्थिति,3 अगस्त से लागू होगा आदेश...उल्लंघन पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

-संवाददाता-
सूरजपुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शिक्षा विभाग में वर्षों से 'व्यवस्था' के नाम पर चल रही गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की अनौपचारिक पदस्थापना व्यवस्था पर जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) लता बेक ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है, शासन द्वारा संलग्नीकरण समाप्त किए जाने के बावजूद जिला एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालयों में कर्मचारियों से कार्य कराए जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डीईओ ने सख्त आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी गैर-शैक्षणिक कर्मचारी अपनी मूल पदस्थ संस्था छोड़कर अन्य कार्यालय में कार्य नहीं करेगा, डीईओ द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को 3 अगस्त 2026 से अपनी मूल पदस्थ संस्था अथवा कार्यालय में उपस्थित होकर वहीं से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी, आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बीईओ कार्यालयों को लेकर मिल रही थीं लगातार शिकायतें-सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक शिकायतें विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सूरजपुर और रामानुजनगर से सामने आ रही थीं। आरोप थे कि कुछ लिपिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी अपनी मूल संस्था में केवल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराते थे,जबकि पूरे दिन बीईओ कार्यालयों में कार्य करते थे,इससे उनकी मूल संस्थाओं का कार्यालयीन कार्य प्रभावित हो रहा था और शासन के आदेशों की भावना पर भी सवाल उठ रहे थे।

पूर्व के सभी व्यवस्था आदेश स्वतः निरस्त- डीईओ के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला कार्यालय अथवा अन्य कार्यालयों में किसी भी प्रकार की 'व्यवस्था' के तहत कार्य कराने संबंधी पूर्व में जारी सभी आदेश स्वतः निरस्त माने जाएंगे, इसका अर्थ है कि अब कोई भी कर्मचारी पूर्व व्यवस्था का हवाला देकर अन्य कार्यालय में कार्य नहीं कर सकेगा।

ऑनलाइन उपस्थिति भी मूल संस्था से होगी-आदेश के अनुसार, केवल ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराकर अन्य स्थान पर कार्य करना स्वीकार्य नहीं होगा,सभी कर्मचारियों को अपनी मूल पदस्थ संस्था में उपस्थित रहकर वहीं से ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

शासन के निर्देशों के पालन पर जोर-डीईओ ने अपने आदेश में लोक शिक्षण संचालनालय के पूर्व निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि संलग्नीकरण समाप्त होने के बाद भी यदि कर्मचारी मूल संस्था में उपस्थित नहीं होते हैं, तो यह शासन के निर्देशों और सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

प्रशासनिक व्यवस्था में माना जा रहा बड़ा बदलाव

शिक्षा विभाग में इस आदेश को वर्षों से चली आ रही अनौपचारिक 'व्यवस्था' पर निर्णायक प्रशासनिक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे स्कूलों और मूल कार्यालयों में कर्मचारियों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी, साथ ही बीईओ कार्यालयों में व्यवस्था के नाम पर चल रही कार्यप्रणाली पर भी प्रभावी रोक लग सकेगी।

जेल,बर्खास्तगी और फिर 7.7 एकड़ जमीन! सहकारिता तंत्र में कौन देता रहा संरक्षण?

पशुपालन ऋण से धान शॉर्टेज तक आखिर किसके संरक्षण में फलता-फूलता रहा सहकारिता का खेल?

एफआईआर,बर्खास्तगी,फिर बढ़ती संपत्ति! भैयाथान की समितियों पर आखिर किसका था संरक्षण?

सोनपुर से शिवप्रसादनगर तक धान शॉर्टेज,पशुधन ऋण और 7.7 एकड़ जमीन ने खड़े किए बड़े सवाल

भैयाथान सहकारिता का रहस्य, एफआईआर के बाद भी कैसे बढ़ती रही संपत्ति?

सहकारिता का 'सिस्टम' या संरक्षण का खेल? एफआईआर,बर्खास्तगी और करोड़ों की संपत्ति पर उठे सवाल

धान शॉर्टेज,पशुधन ऋण और संयुक्त जमीन तक क्या पूरे नेटवर्क की होगी निष्पक्ष जांच?

सोनपुर-शिवप्रसादनगर समिति,पशुपालन ऋण प्रकरण,धान शॉर्टेज,संयुक्त भूमि रिकॉर्ड और पुनर्बहाली की कवायदों के बीच पूरे तंत्र की निष्पक्ष जांच की मांग तेज

ओंकार पाण्डेय

सूरजपुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की भैयाथान शाखा के अंतर्गत संचालित कई प्राथमिक कृषि साख समितियां वर्षों से विवादों में रही हैं, लगभग हर धान खरीदी सत्र के बाद किसी न किसी समिति में धान शॉर्टेज, स्टॉक सत्यापन, जांच,निलंबन या वित्तीय अनियमितताओं की चर्चाएं सामने आती रही हैं, लेकिन समय बीतने के साथ अधिकांश मामले ठंडे पड़ जाते हैं और अगले सीजन में फिर नए सवाल खड़े हो जाते हैं,इन विवादों के केंद्र में बार-बार कुछ नाम सामने आते रहे हैं,इनमें सोनपुर समिति,शिवप्रसादनगर समिति,पशुपालन ऋण वितरण प्रकरण,धान खरीदी व्यवस्था और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई प्रमुख हैं,अब उपलब्ध दस्तावेजों, न्यायालयीन रिकॉर्ड और राजस्व अभिलेखों को एक साथ देखने पर कई महत्वपूर्ण सवाल उभरते हैं।

पहला अध्याय - सोनपुर समिति से शुरू हुआ विवाद

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोनपुर में वर्ष 2022 के दौरान किसानों ने शिकायत की कि पशुपालन ऋण वितरण में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं,शिकायत में आरोप था कि पात्र किसानों को ऋण नहीं मिला जबकि कुछ मामलों में कथित रूप से नियमों के विपरीत ऋण स्वीकृत किए गए,कलेक्टर सूरजपुर ने शिकायत को गंभीर मानते हुए जांच दल गठित किया,जांच के बाद प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ी,समिति के रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि कथित रूप से 71 हितग्राहियों को नियमों के विपरीत लगभग 1.88 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किया गया,जिससे समिति को आर्थिक क्षति होने की बात कही गई। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हुई।

एफआईआर दर्ज, मामला पहुंचा न्यायालय

04 जनवरी 2023 को झिलमिली (भैयाथान) थाना में अपराध क्रमांक 04/2023 दर्ज किया गया,एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 34, 409 और 420 के तहत अपराध दर्ज हुआ तथा आरोपियों में अजीत सिंह, साधना कुशवाहा और मन्नूलाल के नाम दर्ज हैं, एफआईआर दर्ज होना अपने-आप में दोष सिद्ध होना नहीं है, लेकिन यह दर्शाता है कि जांच एजेंसी ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर आपराधिक जांच शुरू की।

सेवा समाप्ति का आदेश

एफआईआर के साथ-साथ विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई हुई,सोनपुर समिति द्वारा जारी आदेश में साधना कुशवाहा की सेवा समाप्त की गई,आदेश में उल्लेख है कि वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के दौरान लगभग 3559.93 क्विंटल धान शॉर्टेज पाया गया, पशुपालन ऋण वितरण में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए,समिति हितों की उपेक्षा तथा सेवा नियमों के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई, यही वह बिंदु था,जहाँ यह मामला केवल विभागीय कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा।

सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट की कार्यवाही- एफआईआर के बाद जमानत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया,सत्र न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए नियमित जमानत याचिका अस्वीकार कर दी,इसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा, 13 दिसंबर 2023 की कार्यवाही में बचाव पक्ष ने कहा कि लाभार्थियों द्वारा लगभग आधी ऋण राशि वापस कर दी गई है,लेकिन हाईकोर्ट ने पाया कि यह तथ्य मूल जमानत आवेदन में स्पष्ट रूप से नहीं था,इसलिए अतिरिक्त हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया,अर्थात न्यायालय ने उस दावे को उसी समय स्वीकार नहीं किया बल्कि उसका दस्तावेज़ी समर्थन मांगा।

अब सामने आई जमीन की कहानी- इसी बीच राजस्व रिकॉर्ड में एक और तथ्य सामने आया, उपलब्ध फार्मर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड में हदीश मोहम्मद और साधना कुशवाहा के नाम से संयुक्त रूप से कृषि भूमि दर्ज दिखाई देती है,रिकॉर्ड में कई खसरा नंबर दर्ज हैं और कुल कृषि रकबा लगभग 7.7 एकड़ (करीब 3.13 हेक्टेयर) के आसपास बताया गया है,यह रिकॉर्ड केवल भूमि का स्वामित्व दर्शाता है,भूमि 2025 खरीदी गई करोडो के मूल्य पर,धन का स्रोत क्या था? लेकिन उपलब्ध एफआईआर,विभागीय कार्रवाई और बाद में सामने आए भूमि रिकॉर्ड को देखते हुए स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि यदि किसी प्रकार का संदेह है तो संबंधित एजेंसियां आय के स्रोत और भूमि खरीद की स्वतंत्र जांच करें।

सेवा समाप्ति के बाद सबसे बड़ा सवाल

दस्तावेज़ बताते हैं कि सेवा समाप्ति का आदेश जारी हुआ,लेकिन स्थानीय स्तर पर यह चर्चा लगातार बनी रही कि बाद में कथित रूप से 'व्हाइट कार्ड एंट्री' कैसे हुई,यदि वास्तव में सेवा समाप्ति के बाद किसी भी रूप में कार्य से पुनः जुड़ाव हुआ,तो उसका आदेश क्या था? किस अधिकारी ने अनुमति दी? क्या समिति के रिकॉर्ड में इसका उल्लेख है? इन सवालों का स्पष्ट सार्वजनिक उत्तर अभी तक सामने नहीं आया।

2025 की धान खरीदी और नया विवाद

वर्ष 2025 के धान खरीदी सत्र में फिर कई समितियां चर्चा में आई,स्थानीय स्तर पर आरोप लगे कि कुछ धान खरीदी केंद्रों में रिकॉर्ड के अनुसार धान अधिक था लेकिन वास्तविक स्टॉक कम पाया गया,जांच के लिए तहसीलदार,एसडीएम और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की टीम बनाई गई,स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में कुछ केंद्रों पर कमी मिली,बाद की जांच में वही स्टॉक पूरा पाया गया,यदि ऐसा हुआ,तो यह जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है,हालांकि इस संबंध में अंतिम विभागीय निष्कर्ष सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

कल पढ़िए - भाग 2

- क्या धान शॉर्टेज और जमीन के बीच कोई संबंध जांच का विषय बना?
- अप्रैल 2024 में नई Hyundai certa की डिलीवरी का सोशल मीडिया पोस्ट और उससे उठे सवाल।
- भैयाथान शाखा की समितियों में बार-बार वही नाम क्यों चर्चा में आते हैं?
- वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही पर उठ रहे प्रश्न।
- और क्या सहकारिता विभाग पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराएगा?

रामानुजनगर को मिली ढाई करोड़ की स्वास्थ्य सौगात

नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के लिए 2.50 करोड़ रुपये स्वीकृत,आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा अस्पताल

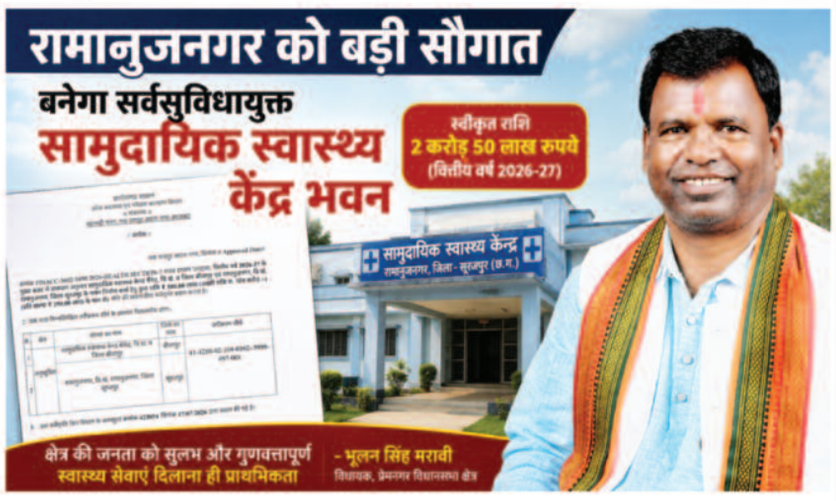

-संवाददाता-

सूरजपुर,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के रामानुजनगर की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हुई है,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,छत्तीसगढ़ शासन ने रामानुजनगर में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के बाद क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को भविष्य में बेहतर, सुलभ और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लंबे समय से रामानुजनगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की मांग उठ रही थी। क्षेत्र के लोगों को उपचार, जांच और अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए कई बार दूरस्थ अस्पतालों का रुख करना पड़ता था,ऐसे में नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की स्वीकृति को क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा नया अस्पताल भवन-स्वीकृत राशि से बनने वाला नया अस्पताल भवन आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुरूप विकसित किया जाएगा,भवन में मरीजों के लिए बेहतर उपचार व्यवस्था,आवश्यक जांच सुविधाएं,पर्याप्त वार्ड,चिकित्सा कक्ष तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीणों को समय पर उपचार भी उपलब्ध हो सकेगा।

हजारों ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ- नए भवन के निर्माण के बाद रामानुजनगर के साथ-साथ आसपास की अनेक ग्राम पंचायतों के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। गंभीर मरीजों, गर्भवती महिलाओं,बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिक एवं सामुदायिक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी,जिससे बड़े अस्पतालों पर निर्भरता भी कम होगी।

लगातार प्रयासों का मिला परिणाम- बताया गया है कि प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने इस परियोजना की स्वीकृति के लिए शासन स्तर पर लगातार प्रयास किए,उनके प्रस्ताव और पहल के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट प्रावधान के अंतर्गत इस परियोजना को मंजूरी दी गई।

क्षेत्र में खुशी का माहौल-अस्पताल भवन की स्वीकृति की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों,सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों में खुशी का माहौल है,लोगों ने इसे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए राज्य शासन एवं विधायक के प्रयासों की सराहना की है।

विधायक बोले...जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देना हमारी प्राथमिकता-विधायक भूलन सिंह मरावी ने कहा कि क्षेत्र की जनता को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, उन्होंने कहा कि नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण से रामानुजनगर क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी,उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य,शिक्षा,सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु उनके प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

जांच या शिकायतकर्ता से जवाब-तलब?

एफएमडी टीकाकरण जांच पर उठे नए सवाल

रायपुर से आई जांच समिति के रवैये पर शिकायतकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप,फोन पर दबाव बनाने और कार्यालय नहीं बुलाने का दावा

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,02 अगस्त 2026 (घटती-घटना)। पशु विभाग के बहुचर्चित एफएमडी (फुट एंड माउथ डिजीज) टीकाकरण अभियान में कथित अनियमितताओं की जांच अब स्वयं सवालों के घेरे में आ गई है,शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जांच के लिए गठित टीम का रवैया निष्पक्ष जांच करने के बजाय शिकायतकर्ता से ही जवाब-तलब करने जैसा रहा, उनका दावा है कि रायपुर से गठित जांच समिति के अध्यक्ष एवं अपर संचालक ने उन्हें फोन कर कार्यालय नहीं आने की बात कही और कई सवाल पूछते हुए दबाव बनाने का प्रयास किया। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं,तो मामला केवल कथित टीकाकरण अनियमितताओं तक सीमित न रहकर जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर सकता है।

पत्र में बुलाया... फोन पर आने से रोका?

शिकायतकर्ता के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण,रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 281/जांच/कोरिया-खड़गवां/2026-27,दिनांक 27 जुलाई 2026 में स्पष्ट उल्लेख था कि 30 जुलाई 2026 को गठित जांच समिति कोरिया जिले में पहुंचकर जांच करेगी तथा शिकायतकर्ता को आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने का आग्रह किया गया था,लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि पत्र के विपरीत जांच समिति के अध्यक्ष एवं अपर संचालक ने स्वयं फोन कर उन्हें कार्यालय नहीं आने के लिए कहा और उसी दौरान कई सवाल पूछे।

फोन पर पूछे गए सवालों पर उठे विवाद

शिकायतकर्ता का दावा है कि फोन पर उनसे कहा गया की जब तुम्हारे यहां टीकाकरण करने गए थे,वह कौन-सी तारीख थी? तुमने टीकाकरण क्यों नहीं कराया? टीकाकरण कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है, पूरे क्षेत्र में 60 हजार पशु हैं, क्या सिर्फ तुम्हारे ही पशु देखें? शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने जवाब दिया कि यदि विभाग की टीम गांव में टीकाकरण करने ही नहीं पहुंची, तो पशुपालक स्वयं विभाग के पीछे-पीछे घूमकर टीकाकरण कैसे कराएंगे,उनके अनुसार टीकाकरण कराना विभाग की जिम्मेदारी है,न कि पशुपालकों की।

जांच से पहले शिकायतकर्ता पर ही सवाल क्यों?-इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठने लगे हैं,यदि जांच समिति का गठन समाचारों में प्रकाशित आरोपों, विभागीय अभिलेखों और जमीनी स्थिति का सत्यापन करने के लिए किया गया था, तो शिकायतकर्ता से फोन पर इस प्रकार पूछताछ क्यों की गई? यदि पत्र में शिकायतकर्ता को उपस्थित होने का आग्रह किया गया था,तो बाद में फोन पर कार्यालय नहीं आने की बात क्यों कही गई? दोनों स्थितियों के बीच दिखाई देने वाला यह विरोधाभास जांच प्रक्रिया को लेकर नई शंकाएं पैदा कर रहा है।

जांच नहीं,दबाव बनाने की कोशिश का आरोप- शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि जांच समिति का व्यवहार ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका उद्देश्य तथ्यों की निष्पक्ष जांच करना नहीं,बल्कि शिकायतकर्ता को मानसिक रूप से दबाव में लाना था, शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि जांच समिति के अध्यक्ष एवं अपर संचालक के साथ हुई पूरी टेलीफोन वार्ता की रिकॉर्डिंग उनके पास सुरक्षित है,उनका कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर यह रिकॉर्डिंग सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी, हालांकि,इस रिकॉर्डिंग की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और इसकी सत्यता का निर्धारण सक्षम जांच अथवा विधिक प्रक्रिया के बाद ही संभव होगा।

जांच प्रक्रिया पर उठ रहे प्रमुख सवाल- विभागीय पत्र में शिकायतकर्ता को उपस्थित होने का आग्रह किया गया था, तो फोन पर कार्यालय नहीं आने की बात क्यों कही गई? क्या जांच समिति का उद्देश्य शिकायत की निष्पक्ष जांच करना था या शिकायतकर्ता से ही जवाब-तलब करना? यदि कई क्षेत्रों में वास्तविक टीकाकरण नहीं हुआ,तो ऑनलाइन पोर्टल पर 100 प्रतिशत उपलब्धि कैसे दर्ज हुई? क्या जांच के दौरान विभागीय रिकॉर्ड,अपलोड किए गए फोटो, पशुपालकों के बयान और जमीनी स्थिति का समुचित सत्यापन किया गया? यदि शिकायतकर्ता के पास मौजूद रिकॉर्डिंग प्रमाणित होती है,तो क्या जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी अलग से जांच होगी?

पक्ष जानने का प्रयास- इस मामले में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. लक्ष्मी अजगले का पक्ष जानने के लिए समाचार प्रकाशित होने से पूर्व उपलब्ध मोबाइल नंबर 8516875725 पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। उनका पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

नजर अब जांच रिपोर्ट पर...

एफएमडी टीकाकरण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर पहले ही शासन स्तर पर जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, अब शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए नए आरोपों ने जांच प्रक्रिया को भी बहस के केंद्र में ला दिया है,यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो मामला केवल टीकाकरण अभियान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिकायतकर्ताओं के साथ प्रशासनिक व्यवहार और जांच की निष्पक्षता पर भी व्यापक सवाल खड़े करेगा,वहीं यदि आरोप गलत पाए जाते हैं,तो यह भी जांच रिपोर्ट के माध्यम से स्पष्ट होना आवश्यक होगा,ऐसी स्थिति में सभी पक्षों की बात सामने आने और आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार महत्वपूर्ण होगा।

टॉक्सिक में इंटीमेट सीन के लिए कियारा को मिल रही ट्रोलिंग पर हुमा कुरैशी ने तोड़ी चुप्पी,बोलीं...ये घिनौनी बात...

यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक का गाना तबाही रिलीज होने के बाद से कियारा आडवाणी के इंटीमेट सीन करने पर काफी आलोचना हो रही है। अब हुमा कुरैशी ने इस पर रिएक्ट किया है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को टॉक्सिक फिल्म के गाने तबाही में यश के साथ इंटीमेट सीन करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों ने एक शादीशुदा महिला और मां होने के नाते उनके फैसलों पर सवाल उठाए हैं।

वहीं यश जो खुद भी शादीशुदा हैं, को उन्हीं सीन के लिए बहुत कम आलोचना झेलनी पड़ी है। इस बारे में बात करते हुए हुमा कुरैशी ने कहा कि उन्हें यकीन है कि फिल्म रिलीज होने के बाद उससे जुड़ी महिलाओं की ही जीत होगी, यानी फिल्म आलोचना करने वालों का मुंह बंद कर देगी।

हुमा ने किया कियारा आडवाणी का बचाव

एक इंटरव्यू में इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हुमा ने कहा, यह बहुत गलत और घिनौनी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म से जुड़ी महिलाएं,यानी एक्ट्रेस और डायरेक्टर,आखिर में बाजी मारेंगी। किसी चीज का बचाव करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप बातों से लोगों की सोच नहीं बदल सकते। मैं बस फिल्म को ही अपनी बात कहने दूंगी।

सोशल मीडिया पर हुई कियारा की आलोचना

यश की फिल्म टॉक्सिक का पहला गाना तबाही रिलीज होने के बाद से ही कियारा आडवाणी को म्यूजिक वीडियो में अपने इंटीमेट और सेंसुअल सीन्स के लिए काफी आलोचना और भद्दे कमेंट्स का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, यह विरोध जल्द ही सिर्फ एक्ट्रेस तक ही सीमित नहीं रहा; ट्रोलर्स ने उनके पति सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी निशाना बनाया और उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी ऐसे ही कमेंट्स किए।

टॉक्सिक के बारे में

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी टॉक्सिक एक एक्शन फिल्म है। इस फ़िल्म में यश के साथ पांच एक्ट्रेसेस अहम किरदारों में हैं। कियारा, नयनतारा, तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत और हुमा कुरैशी। फिल्म 26 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मॉम का बन रहा सीक्वल,एक्ट्रेस खुशी कपूर निभाएगी लीड रोल

महान अभिनेत्री श्रीदेवी की फिल्म 'मॉम' 2017 में आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अब करीब 9 साल बाद इसका सीक्वल बनने जा रहा है, जिसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खुशी कपूर अब फिल्म 'मॉम 2' में लीड रोल निभाने जा रही हैं। यह 2017 की हिट फिल्म मॉम का सीक्वल है और इसे नवंबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है। इस फिल्म को उनके पिता बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसकी शूटिंग नोएडा और ग्रीस में हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक,'मॉम 2' का कनेक्शन श्रीदेवी के उस यादगार किरदार से जुड़ा होगा, जिसने उन्हें खास पहचान दिलाई थी। 'मॉम' श्रीदेवी की आखिरी फिल्म थी,ऐसे में यह प्रोजेक्ट खुशी कपूर के लिए काफी इमोशनल और खास माना जा रहा है, क्योंकि वह अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाती नजर आएंगी।खुशी कपूर ने 'द आर्चीज' से डेब्यू किया था, लेकिन 'नादानियां' और 'लवयापा' जैसे प्रोजेक्ट्स को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। ऐसे में 'मॉम 2' को उनके करियर का बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है।रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म के शुरुआती फुटेज देखने वाले एक सूत्र ने खुशी की एक्टिंग में काफी सुधार बताया है। उन्होंने कहा कि खुशी इस बार ज्यादा इमोशनल डेप्थ के साथ नजर आ रही हैं और कहीं-कहीं श्रीदेवी की झलक भी दिखती है।

फ्रेंडशिप डे पर छलका अनिल कपूर का प्यार

फ्रेंडशिप डे 2026 के मौके पर बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर ने अपनी पुरानी और खास दोस्ती को याद करते हुए दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक के लिए एक भावुक पोस्ट साझा किया। अनिल कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने दोस्त सतीश कौशिक को याद करते हुए एक दिल छू लेने वाला नोट लिखा, जिसमें उन्होंने वर्षों पुराने रिश्ते, साथ बिताए पलों और दोस्ती की अहमियत को बयां किया। अनिल कपूर और सतीश कौशिक की दोस्ती बॉलीवुड की सबसे चर्चित दोस्तियों में से एक रही है। दोनों कलाकारों ने न सिर्फ कई फिल्मों में साथ काम किया, बल्कि निजी जिंदगी में भी एक-दूसरे के बेहद करीब रहे। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर अनिल कपूर ने बताया कि सतीश कौशिक उनके लिए सिर्फ एक सहकर्मी नहीं बल्कि जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में साथ खड़े रहने वाले सच्चे दोस्त थे। अनिल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सतीश कौशिक की याद में एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने अपनी फिल्म 'दीवाना मस्ताना' का एक वीडियो क्लिप भी साझा किया, जिसमें सतीश कौशिक ने लोकप्रिय किरदार 'पप्पू पेजर' निभाया था। अभिनेता ने लिखा कि उन्हें सतीश की हंसी-मजाक करने की आदत,उनकी ऊर्जा और शानदार प्रतिभा की बहुत याद आती है। अनिल कपूर ने अपने भावुक संदेश में कहा कि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है,जिसे इंसान किसी भी परेशानी, उदासी या खुशी के पल में सबसे पहले याद करता है। उन्होंने कहा कि सतीश कौशिक उनके लिए वही खास दोस्त थे,जिनसे बात करने के बाद जिंदगी थोड़ी आसान और खुशहाल महसूस होती थी।

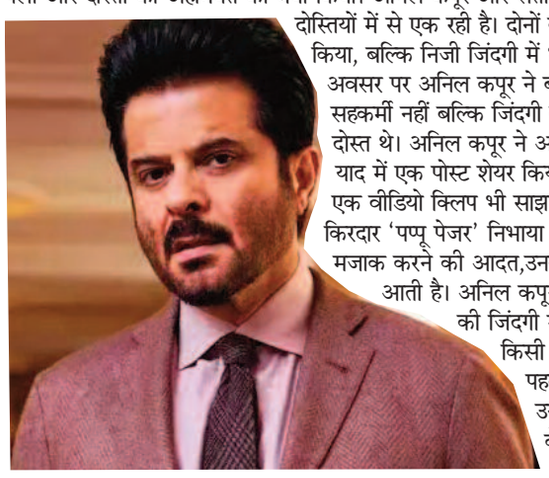

उन्होंने लिखा कि सतीश के साथ उनका रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था। दोनों ने अपने करियर के शुरुआती दौर से लेकर सफलता तक का सफर साथ तय किया। उन्होंने साथ में संघर्ष किया, सफलता का आनंद लिया और कई यादगार पल साझा किए। अनिल कपूर ने कहा कि ऐसी दोस्ती जीवन में बहुत कम लोगों को मिलती है और यह किसी आशीर्वाद से कम नहीं होती। सतीश कौशिक का निधन 9 मार्च 2023 को गुरुग्राम में हार्ट अटैक के कारण हुआ था। उनके निधन ने बॉलीवुड सहित पूरे फिल्म जगत को झकझोर दिया था। सतीश कौशिक ने अपने अभिनय,निर्देशन और लेखन से हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई थी। उनके जाने के बाद उनके करीबी दोस्त और कलाकार अक्सर उन्हें याद करते रहते हैं।

अनिल कपूर और सतीश कौशिक की दोस्ती की शुरुआत फिल्मी सफर के शुरुआती दिनों में हुई थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म 'मिस्टर इंडिया' में सतीश कौशिक ने 'कैलेंडर' का किरदार निभाकर खूब लोकप्रियता हासिल की थी। यह किरदार आज भी दर्शकों के बीच याद किया जाता है। इसके अलावा दोनों कलाकारों ने 'दीवाना मस्ताना' में भी साथ काम किया,जिसमें सतीश कौशिक का 'पप्पू पेजर' किरदार काफी पसंद किया गया था। फिल्म 'राम लखन' में भी दोनों की जोड़ी नजर आई थी। पर्दे पर उनकी दोस्ती और कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों ने खूब सराहा। फ्रेंडशिप डे पर अनिल कपूर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। फैंस ने भी सतीश कौशिक को याद करते हुए उनकी दोस्ती की मिसाल दी। लोगों ने कहा कि सच्ची दोस्ती समय और दूरी से खत्म नहीं होती, बल्कि यादों के रूप में हमेशा जिंदा रहती है। अनिल कपूर का यह भावुक संदेश बॉलीवुड की उस खूबसूरत दोस्ती को दर्शाता है, जो सालों बाद भी दिलों में कायम है।

लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी की फ़िल्म डीसी का ट्रेलर रिलीज़,7 अगस्त को होगी रिलीज़

लोकेश कनगराज डीसी नाम की फ़िल्म से एक एक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं। इस फ़िल्म को अरुण मथेश्वरन डायरेक्ट कर रहे हैं और यह 7 अगस्त 2026 को रिलीज़ होगी। फ़िल्म में वामिका गब्बी फीमेल लीड रोल में हैं।

मेकर्स ने फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया और इसने फ़िल्म प्रेमियों के बीच ज़बरदस्त दिलचस्पी पैदा की। 2 मिनट 32 सेकंड के ट्रेलर में देवदास (लोकेश कनगराज) को दिखाया गया है,जो न सिर्फ़ अपने अतीत से, बल्कि कानून से भी भागने की कोशिश करता है। सब कुछ तब बिखर जाता है जब एक पुलिस अफ़सर की हत्या हो जाती है और उसके कातिल की तलाश शुरू होती है। इसके अलावा,एक दूसरा मामला भी है जिसमें एक ऐसे क्रिमिनल गैंग की जांच शामिल है जिसने बेकार पड़े हथियार चुरा लिए हैं। इन दोनों मामलों के धीरे-धीरे आपस में जुड़ने से, देवदास क्रिमिनल्स,चरमपंथियों और पुलिस के बीच फँस जाता है।

किस्मत के एक अजीब मोड़ पर चंद्रा (वामिका गब्बी) की मुलाक़ात देवदास से होती है। हालाँकि, किस्मत की यह मुलाक़ात एक रिश्ते में बदल जाती है,जो धोखे,त्याग और लगातार बने रहने वाले ख़तरे की वजह से मुश्किल हो जाता है। फिर,आपकी मुलाक़ात पार्वती (संजना कृष्णमूर्ति) से होती है,जो देवदास की उथल-पुथल भरी ज़िंदगी में कुछ शांति लाती हुई लगती है। ट्रेलर इस सवाल के साथ खत्म होता है- जब कोई अपराध होता है,तो पुलिस उसे सुलझाने के लिए आगे आती है। लेकिन जब पुलिस ही कोई अपराध करती है,तो उस पर सवाल उठाने के लिए कौन आगे आएगा?

खेल समाचार

जसप्रीत बुमराह की जगह टीम इंडिया में आएगा जम्मू-कश्मीर का घातक गेंदबाज

नई दिल्ली,02अगस्त 2026। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार पेसर और टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 15 अगस्त से गॉल में श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने जा रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुमराह अपने बाएं घुटने में अभी भी खिंचाव और दर्द महसूस कर रहे हैं। बीसीसीआई उनके मामले में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहता और उन्हें पूरी तरह फिट होने की सलाह दी गई है। बुमराह ने भारत के लिए आखिरी टेस्ट मुकाबला नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेला था ऐसे में श्रीलंका जैसी महत्वपूर्ण सीरीज से उनका बाहर होना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

आकिब नबी को मिल सकता है मौका

जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बाद सेलेक्टर जल्द ही उनके विकल्प का ऐलान कर सकते हैं,जिसमें 29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी दार का नाम सबसे आगे चल रहा है। बारामूला से ताल्लुक रखने वाले और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल चुके आकिब ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अपने

धारदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। हालांकि, उन्हें अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वे भारतीय टीम में शामिल किए जाने के प्रबल दावेदार बन चुके हैं।

कमाल का आकिब का रिकॉर्ड

आकिब नबी का प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने 43 फर्स्ट क्लास मुकाबलों की 71 पारियों में 18.63 के शानदार औसत और 2.90 की इकोनॉमी रेट से कुल 162 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 16 बार एक पारी में पांच विकेट और 4 बार मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा किया है जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 24 रन देकर 7 विकेट रहा है। इसके अलावा उन्होंने 36 लिस्ट-ए मैचों में 56 विकेट और 39 टी20 मुकाबलों में 43 विकेट हासिल किए हैं जहां उनका गेंदबाजी औसत 27.37 और 25.27 का रहा है।

पिछले दो सीजन में मचाया कमाल

घरेलू सत्र में आकिब का बल्ला और गेंद दोनों चमके हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी के 2024-25 सीजन के 8 मैचों में 44 विकेट झटके थे। इसके अगले ही सत्र यानी 2025-26 के रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 10 मैचों में रिकॉर्ड 60 विकेट चटकाए और अपनी टीम जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी ट्रॉफी का ऐतिहासिक खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस सीजन में उन्होंने 7 बार पांच विकेट लेने का कारनामा किया और बल्लेबाजी में दो अर्धशतकों की मदद से 245 रन भी बनाए। हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया-ए टीम के सदस्य रहते हुए उन्होंने गॉल में खेले गए दो प्रथम श्रेणी मैचों में 6 विकेट चटकाए थे जिसमें एक पारी में 58 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

इससे पहले जून 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के दौरान भी आकिब को भारतीय टीम में शामिल करने की मजबूत मांग उठी थी लेकिन बीसीसीआई सेलेक्टर्स ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था।

भारत-मलेशिया हॉकी सीरीज का आगाज,बेंगलुरु में होगी 8 मैचों की जंग

बेंगलुरु,02अगस्त 2026। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक अहम सीरीज खेलने जा रही है। भारत सात से 13 अगस्त तक बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र में मलेशिया की अंडर-21 पुरुष हॉकी टीम की मेजबानी करेगा। दोनों देशों के बीच होने वाली यह आठ मैचों की सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव हासिल करने का बड़ा अवसर मानी जा रही है। इस सीरीज में मलेशिया की अंडर-21 टीम भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के खिलाफ पांच मुकाबले खेलेगी,जबकि तीन मैच साई टीम के साथ खेले जाएंगे। भारतीय टीम के लिए यह सीरीज आने वाले बड़े टूर्नामेंटों की तैयारी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। कोचिंग स्टाफ इस दौरान खिलाड़ियों की फिटनेस, रणनीति और मैदान पर प्रदर्शन को परखने का मौका मिलेगा। भारतीय जूनियर टीम मलेशिया के खिलाफ सात,आठ,10,12 और 13 अगस्त को मुकाबले खेलेगी। वहीं मलेशियाई टीम साई टीम के खिलाफ तीन, पांच और 15 अगस्त को मैदान पर उतरेगी। लगातार होने वाले इन मुकाबलों से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल में खेलने का अनुभव मिलेगा और टीम की कमजोरियों को सुधारने का अवसर भी प्राप्त होगा। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच फ्रेडरिक सोयेज ने इस सीरीज को बेहद अहम बताया है। उन्होंने कहा कि मलेशिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले आगामी एशिया कप की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कोच के अनुसार,टीम ने हाल ही में बेल्जियम दौरे के दौरान कई सकारात्मक पहलुओं पर काम किया था और अब इस सीरीज के जरिए उन सुधारों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स में चमक बिखेरने के बाद भारतीय एथलीटों की स्वदेश वापसी

नई दिल्ली,02अगस्त 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय एथलीटों का पहला जत्था रविवार को स्वदेश लौट आया। इसमें देश की स्टार वेटलिफ्टर और ओलंपिक पदक विजेता साइखोम मीराबाई चानू तथा लवप्रीत सिंह समेत कई खिलाड़ी शामिल रहे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचते ही खिलाड़ियों का सैकड़ों प्रशंसकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर मौजूद फैंस ने खिलाड़ियों के समर्थन में नारे लगाए और उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। भारतीय खिलाड़ियों के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी पहुंचे थे। खिलाड़ियों ने भी प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया और अपने अनुभव साझा किए। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए महिलाओं के 49 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यह उनका लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल है। इससे पहले भी वह इस प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। मीराबाई चानू का प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा। उन्होंने अपने अनुभव, तकनीक और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि ने भारतीय खेल जगत में एक बार फिर उनकी विशेष पहचान को मजबूत किया है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई लंबे समय से भारतीय वेटलिफ्टिंग की सबसे बड़ी उम्मीदों में शामिल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाली मीराबाई ने कई बड़े मंचों पर देश का नाम रोशन किया है।

तिलक वर्मा दिलीप ट्रॉफी में साउथ ज़ोन की कप्तानी करेंगे; रिकी भुई को उप-कप्तान बनाया

विशाखापत्तनम,02अगस्त 2026। भारत के टी20 आई उप-कप्तान तिलक वर्मा को रविवार को आगामी दलीप ट्रॉफी के लिए 15 सदस्यीय साउथ ज़ोन टीम का कप्तान बनाया गया। यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में खेला जाएगा। आंध्र के बल्लेबाज़ रिकी भुई टीम के उप-कप्तान होंगे, जबकि आंध्र के अनुभवी लेवल 2 कोच विक्रम वर्मा को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तिलक हाल ही में उस भारतीय टी20 आई टीम का हिस्सा थे जिसने ज़िम्बाब्वे

को 3-0 से हराया था।

भाग-2

अस्पताल बढ़े, डॉक्टर बढ़े... स्वास्थ्य व्यवस्था को मिली नई मजबूती

दाई साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव

- 11 उप स्वास्थ्य केंद्र, 43 पीएचसी, 2 सीएचसी,
- 5 सिविल अस्पताल, 3 मातृ-शिशु चिकित्सालय
- 1000+ डॉक्टरों की भर्ती
- 525 नर्स और पेरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति
- 3000+ स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती
- मातृ मृत्यु दर 146 से घटकर 124
- 450 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली
- मलेरिया सूचकांक 5.21 से घटकर 0.90
- 4500+ पंचायतें हुई टीबी मुक्त

11	43	2						
उप स्वास्थ्य केंद्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	सिविल अस्पताल	मातृ-शिशु चिकित्सालय	मानसिक चिकित्सालय	नेत्र चिकित्सालय	इमरजेंसी हेल्थ क्लीनिक सामिताव	100 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल

ढाई वर्षों में स्वास्थ्य अधोसंरचना का विस्तार

1000 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती, मातृ मृत्यु दर में सुधार का दावा

11 नए उप स्वास्थ्य केंद्र,43 पीएचसी,हजारों नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति,मलेरिया और टीबी नियंत्रण पर विशेष फोकस

ढाई साल का रिपोर्ट कार्ड 'अस्पताल बढ़े, डॉक्टर बढ़े...अब स्वास्थ्य व्यवस्था को मिली नई मजबूती

स्वास्थ्य ढांचे में विस्तार,भर्ती में तेजी और मातृ-शिशु स्वास्थ्य पर विशेष फोकस

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने गिनाईं उपलब्धियां...

कहा...सिर्फ भवन नहीं,गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देना सरकार का लक्ष्य

हजारों नर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति,मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी का दावा

न्यूज डेस्क

रायपुर,02 अगस्त 2026
(घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की उपलब्धियों का विस्तृत उल्लेख करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने लगभग ढाई वर्ष के कार्यकाल में स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार,चिकित्सकों की भर्ती, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकेतकों में हुए बदलावों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया,उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल भवन निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि डॉक्टर,नर्स,पैरामेडिकल स्टाफ, आधुनिक उपकरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता दी।

प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना का हुआ व्यापक विस्तार-स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से अनेक नए स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना एवं पुराने अस्पतालों के उन्नयन का कार्य किया गया,उन्होंने बताया कि इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा 11 नए उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए,43 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किए गए,2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए,5 सिविल अस्पतालों की स्थापना की स्वीकृति दी गई,3 मातृ एवं शिशु चिकित्सालय स्वीकृत किए गए,एक मानसिक चिकित्सालय स्थापित किया गया,एक क्षेत्रीय नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की गई,चार इमरजेंसी हेल्थ क्लीनिक प्रारंभ किए गए,100 बिस्तरों वाले जिला चिकित्सालय के निर्माण एवं विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई,मंत्री ने कहा कि इन संस्थानों का उद्देश्य केवल भवन तैयार करना नहीं बल्कि उनमें पर्याप्त मानव संसाधन एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है।

45 स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन

उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में 45 स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन किया गया है,इन संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पदस्थापना,आधुनिक उपकरण,नए भवन,ऑपरेशन थिएटर,मातृ एवं शिशु सेवाओं का विस्तार,जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं,मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता केवल भवनों से नहीं बल्कि वहां उपलब्ध सेवाओं से तय होती है।

सिर्फ सीमेंट और ईंट का भवन बनाना पर्याप्त नहीं...

प्रेस वार्ता के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा...यदि अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं,नर्स नहीं हैं,उपकरण नहीं हैं और मरीज को इलाज नहीं मिल रहा है,तो केवल सीमेंट और ईंट का भवन बना देने से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं होती,उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के हर पहलू पर समान रूप से काम किया है।

डॉक्टरों की भर्ती में आई तेजी...

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में वर्षों से रिक्त पड़े पदों को भरने की दिशा में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई, उन्होंने बताया कि–लगभग 1000 नए डॉक्टरों की भर्ती की गई, मेडिकल ऑफिसर एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियमित नियुक्तियां की गई, वर्तमान में 100 मेडिकल ऑफिसर एवं 100 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नई भर्ती प्रक्रिया जारी है, उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

525 नर्सों की भर्ती,3000 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति

मंत्री ने बताया कि डॉक्टरों के साथ-साथ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की भी बड़े पैमाने पर भर्ती की गई,उन्होंने कहा 525 स्टाफ नर्स एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों की भर्ती व्यापम के माध्यम से पूरी हो चुकी है,एचएम के माध्यम से लगभग 3000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की गई है अथवा अंतिम चरण में है,उन्होंने कहा कि इन नियुक्तियों से जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा।

दूरस्थ क्षेत्रों पर विशेष ध्यान

मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है,उन्होंने कहा कि बस्तर,सरगुजा,वनांचल,आदिवासी क्षेत्र जैसे इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विशेष नीति अपनाई गई है।

बंधपत्र व्यवस्था में बड़ा बदलाव

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मेडिकल विद्यार्थियों की लंबे समय से यह मांग थी कि एमबीबीएस के बाद लागू बंधपत्र की अवधि कम की जाए, सरकार ने दो वर्ष की अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया,उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में नियमित भर्ती होने पर इस व्यवस्था में और सुधार किया जा सकता है।

मातृ मृत्यु दर में सुधार सरकार की बड़ी उपलब्धि

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला तब मातृ मृत्यु दर के मामले में छत्तीसगढ़ देश के सबसे पिछड़े राज्यों में था,उन्होंने बताया पहले मातृ मृत्यु दर 146 थी, वर्तमान में यह घटकर 124 हो गई है,उन्होंने स्वीकार किया कि अभी भी सुधार की आवश्यकता है,लेकिन यह परिवर्तन स्वास्थ्य विभाग के सतत प्रयासों का परिणाम है।

हाई रिस्क प्रेग्नेंसी पर विशेष निगरानी

मंत्री ने कहा कि मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई रणनीति अपनाई,इसके अंतर्गत हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान,नियमित जांच,विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी,संस्थागत प्रसव,पर विशेष ध्यान दिया गया,उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान में भी 10,938 हाई रिस्क गर्भवतियों की पहचान इसी रणनीति का हिस्सा थी।

भारत सरकार से मिला 450 करोड़ का प्रोत्साहन

मंत्री ने बताया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को लगभग 450 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई है, उन्होंने कहा कि यह राशि भविष्य की स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार में उपयोग की जाएगी।

116 एफआरयू केंद्र विकसित किए जाएंगे...

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 116 एफआरयू विकसित किए जा रहे हैं, इन केंद्रों में सुरक्षित प्रसव,सर्जरी,नवजात शिशु की देखभाल,रक्त उपलब्धता, विशेषज्ञ चिकित्सक,जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

मलेरिया नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति

मंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र लंबे समय से मलेरिया प्रभावित रहा है,उन्होंने अपने निजी अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय वे स्वयं भी मलेरिया से प्रभावित हुए थे,उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 में वार्षिक परजीवी सूचकांक 16.80 तक था, बाद में यह घटकर 5.21 हुआ,वर्तमान सरकार के कार्यकाल में यह घटकर 0.90 तक पहुंच गया है, सरकार का लक्ष्य इसे 0.50 से भी नीचे लाना है।

मलेरिया नियंत्रण के लिए बहुआयामी रणनीति

उन्होंने बताया कि घर-घर जांच,रक्त परीक्षण,फॉगिंग,दवा वितरण,मच्छर नियंत्रण, जनजागरूकता अभियान,लगातार चलाए जा रहे हैं,मंत्री ने कहा कि यदि एक भी व्यक्ति की मलेरिया से मृत्यु होती है तो सरकार उसे गंभीरता से लेती है।

टीबी मुक्त पंचायतों में छत्तीसगढ़ अग्रणी

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश की लगभग 4500 पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं,उन्होंने कहा कि टीवी उन्मूलन अभियान में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों तथा स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त भूमिका रही है।

जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की भी हो रही स्क्रीनिंग

मंत्री ने कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग केवल संक्रामक रोगों तक सीमित नहीं है,प्रदेशभर में–उच्च रक्तचाप,मधुमेह,कैंसर,जैसी गैर-संचारी बीमारियों की प्रारंभिक जांच भी बड़े पैमाने पर की जा रही है,इससे गंभीर बीमारियों का समय रहते उपचार संभव हो रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं का नया मॉडल

अपने संबोधन के अंत में इस खंड में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल अस्पतालों की संख्या बढ़ाना नहीं है,बल्कि ऐसी व्यवस्था विकसित करना है जहां–मरीज को समय पर डॉक्टर मिले,जांच उपलब्ध हो,दवाइयां मिलें,विशेषज्ञ सेवाएं मिलें,और ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों को भी शहरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हों,उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाले वर्षों में और भी बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे।

विशेष रिपोर्ट (भाग-3) में पढ़िए...

- 26 जिलों में कीमोथेरेपी सुविधा
- 32 जिलों में निशुल्क डायलिसिस
- 108 एवं एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का विस्तार
- 1297 स्वास्थ्य संस्थानों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन
- आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान
- अटल आरोग्य जांच योजना
- दवा गुणवत्ता नियंत्रण
- अत्याधुनिक 96 करोड़ की इंटीग्रेटेड लैब
- खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाइयां
- और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं।

राज्यपाल डेका और सीएम साय की उपस्थिति में लोकभवन से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ

रायपुर,02 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देशभर में प्रारंभ हुए 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' के तहत राजधानी रायपुर स्थित लोक भवन में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की गरिमामयी उपस्थिति में बड़ी संख्या में युवा, छात्र-छात्राएं, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठन तथा विभिन्न युवा संगठनों के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्त भारत के निर्माण का संकल्प लिया और समाज को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से देशभर के युवाओं को संबोधित करते हुए 100 सप्ताह तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की

सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और यदि युवा नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा,प्रतिभा और क्षमता का सकारात्मक उपयोग करें,तो भारत को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से स्वयं नशामुक्त जीवन अपनाने के साथ-साथ अपने परिवार, मित्रों और समाज को भी इस दिशा में जागरूक करने का आह्वान किया। लोक भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण बड़ी संख्या में उपस्थित युवाओं ने उत्साहपूर्वक देखा। राज्यपाल श्री रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में सभी प्रतिभागियों ने नशामुक्ति की शपथ ली। कार्यक्रम में युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक,मानसिक,सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने,सकारात्मक सोच विकसित करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का संदेश दिया गया। उल्लेखनीय है कि 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' 2 अगस्त 2026 से प्रारंभ होकर आगामी 100 सप्ताह तक देशभर में संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत विद्यालयों,महाविद्यालयों,विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस),राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), माय भारत युवा संगठन तथा अन्य युवा संगठनों के सहयोग से विविध जन-जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। इनमें नशामुक्ति शपथ कार्यक्रम,जागरूकता रैलियाँ, पोस्टर एवं चित्रकला प्रतियोगिताएँ, वाद-विवाद,निबंध लेखन,नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ,लघु फिल्म प्रदर्शन, सोशल मीडिया अभियान तथा सामुदायिक संवाद जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)